● वर्ष-5

● अंक-220

रायपुर, शनिवार
02 मई 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› सुशासन तिहार : गांवों में खत्म...

14 से 16 मई को पहुंचेगा मानसून

जम्मू से लेकर एमपी तक होगी मूसलाधार बारिश; अल-नीनो का दिखेगा असर

नई दिल्ली। मई महीने में देश का मौसम एक साथ राहत और चुनौती दोनों लेकर आ रहा है। किसी क्षेत्र में अधिक गर्मी तो कहीं अधिक बारिश हो सकती है। उत्तर-पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है, जिससे भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी।

पूर्वी भारत में वर्षा का स्वरूप असमान रह सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक बारिश और कुछ में कमी की स्थिति बन सकती है। अलनीनो का असर मानसूनी बारिश पर पड़ेगा, जिसके चलते सामान्य से कम बारिश की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है।

कब होगी मानसून की शुरुआत

मानसून की शुरुआत के संकेत भी साफ हैं। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 14 से 16 मई के बीच पहुंच सकता है। यह सामान्य तिथि के आसपास है, जो मानसून के समय पर आगे बढ़ने की संभावना को मजबूत करता है।

भारत मौसम विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने शुक्रवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर मई के तापमान, बारिश और मानसून की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मई में पूरे देश में औसत वर्षा सामान्य से अधिक रह सकती है। उत्तर-पश्चिम भारत और हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में शुरुआती पखवाड़े में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है।

कहां-कहां बढ़ेगा तापमान

इससे जम्मू-कश्मीर से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान पर नियंत्रण रहेगा एवं लू का असर सीमित हो सकता है। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में तापमान बढ़ने के संकेत हैं, जो अस्थायी रूप से गर्मी को तेज कर सकते हैं। पूर्वानुमान में कहा गया है कि अलग-अलग इलाकों के तापमान में भी असमानता होगी। उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य या उससे कम रह सकता है, जबकि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। ऐसे में रात में भी गर्मी बनी रह सकती है, जिससे लोगों को पूरी राहत नहीं मिलेगी।पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के हिस्सों में हालात विपरीत रह सकते हैं। वहां वर्षा सामान्य से कम रहने की आशंका है।

यह स्थिति कृषि और जल प्रबंधन के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में अचानक भारी बारिश की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात बनने का खतरा बना रहेगा।

आईएमडी ने क्या कहा?

आईएमडी का मानना है कि हिमालय की तराई वाले इलाके, पूर्व के तटीय राज्यों, गुजरात और महाराष्ट्र में लू के दिनों की संख्या सामान्य से ज्यादा रह सकती है। गुजरात, विशेषकर सौराष्ट्र क्षेत्र में तीन से चार दिन तीव्र हीटवेव की संभावना जताई गई है।मौसम के इस मिश्रित असर के पीछे समुद्री कारकों की बड़ी भूमिका है। प्रशांत महासागर में अभी न्यूट्रल स्थिति है, जो धीरे-धीरे अलनीनो की ओर बढ़ रही है। इसके मानसून के दौरान विकसित होने की संभावना है। अल नीनो आमतौर पर भारत में वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करता है और मानसून को कमजोर करता है।

टीम नवीन में दिखेगा नारी वंदन अधिनियम का असर

33 फीसदी महिलाओं को शामिल करने की योजना

■ **4 मई के बाद बीजेपी संगठन और सरकार में दिखाई देंगे कई बदलाव**

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल और असम सहित पांच राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी में कई अहम फैसले होने वाले है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल रहे नितिन नवीन को अपनी टीम का गठन करना, इसके अलावा उत्तरप्रदेश से लेकर बिहार तक कैबिनेट विस्तार पेंडिग है। बीजेपी संगठन और सरकार के हिसाब से मई का महीना कई बड़े बदलाव लेकर आएगा।

बताया जा रहा हैं कि 4 मई के बाद बीजेपी नवीन टीम के साथ यूपी से बिहार तक कैबिनेट गठन को अमलीजामा पहनाने का काम करेगी। लंबे समय से लटके पड़े कई फैसले मई में लागू होने की संभावना है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में फेरबदल शामिल है।

बात दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं,

इसके पहले बीजेपी कैबिनेट विस्तार करके सियासी समीकरण को साधना चाहती है। बिहार में सीएम और डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद अब कैबिनेट विस्तार होना है, इस प्रक्रिया को भी बीजेपी अमलीजामा पहनाना चाहती है? बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने सारी तैयारी कर ली है, जिसे चार मई के बाद किसी भी दिन अमल में लाया जा सकता है?

जेपी नड्डा की जगह नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2025 के आखिर में बने हैं, लेकिन पांच महीने के बाद भी अपनी टीम का गठन नहीं कर सके हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने चार मई के बाद नवीन टीम के गठन का प्लान तैयार किया है। इस तरह संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव करने का है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन के नेतृत्व में जल्द ही एक नई टीम बनने की संभावना है।

माना जा रहा है कि नवीन की टीम में अनुभवी और युवा नेताओं का मिश्रण होगा, ताकि एक संतुलन टीम बन सके। युवाओं के साथ महिलाओं को भी शामिल करने की रणनीति है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 33 फीसदी महिलाओं को शामिल करने की योजना है।

वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी की जगह पर पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन अभी तक उनकी टीम नहीं बनी है। सूत्रों के अनुसार यूपी में खाली पड़ें पदों को भरने के अलावा कुछ फेरबदल भी हो सकता है। इसमें कुछ मौजूदा मंत्रियों की ज़िम्मेदारी में बदलाव की भी संभावना है।

सुशासन तिहार

जनसमस्या निवारण महाभियान शुरू, 10 जून तक 49 स्थानों पर लगेगी चौपाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार की सुशासन को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सुशासन तिहार के जरिए प्रशासन सीधे ग्रामीणों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। शुक्रवार को ग्राम रिसदा से शुरू हुए इस अभियान ने पहले ही दिन सफलता के नए मानक स्थापित किए हैं।इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखना है।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर के बाद भी आवेदकों से फीडबैक लिया जाए कि वे समाधान से संतुष्ट हैं या नहीं।

बंगाल में चुनाव के बाद बवाल: तीन जिलों में भारी हिंसा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होते ही राज्य के विभिन्न हिस्सों से हिंसा की खबरें आने लगी हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जिलों में हिंसा की कम से कम तीन बड़ी घटनाएं दर्ज की गईं। पुलिस ने इन मामलों में जांच शुरू कर दी है।

सीपीआईएम एजेंट पर हमला

मुर्शिदाबाद जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के लोचनपुर में गुरुवार रात खूनी संघर्ष हुआ। यहां सीपीआईएम के पोलिंग एजेंट रूहूल अमीन पर जानलेवा हमला किया गया। पार्टी सूत्रों का आरोप है कि

अमीन एक चाय की दुकान पर बैठे थे। तभी तृणमूल कांग्रेस के एक क्षेत्रीय पदाधिकारी के नेतृत्व में स्थानीय नेताओं के समूह ने उन पर हमला कर दिया। परिजनों के मुताबिक, रूहूल रात में घर से बाहर निकले थे। परिवार का आरोप है कि उन्हें पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में उन्हें स्थानीय लोगों ने बचाया। सीपीआईएम ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में रानीनगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार ने पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया, जिसके बाद अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे।

इस मामले में एक गंभीर आरोप यह भी है कि चाय की दुकान के सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा डिलीट कर दिया गया है। हिंसा की दूसरी घटना मालदा जिले के रतुआ क्षेत्र के उत्तर बालूपुर में सामने आई। यहां भाजपा के मंडल अध्यक्ष महानंदा मंडल पर गुरुवार दोपहर हमला हुआ। भाजपा नेताओं का आरोप है कि संदिग्ध टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मंडल को बीच सड़क पर रोका। इसके बाद उन पर ईंटों से ताबड़तोड़ हमला किया गया।

बंगाल के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान

नई दिल्ली चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर और मगरा हाट पश्चिम क्षेत्रों के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है। आयोग के निर्देशानुसार इन सभी केंद्रों पर 2 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह सात बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इन 15 मतदान केंद्रों में 143-डायमंड हार्बर एसी के चार और 142-मगराहाट पश्चिम एसी के 11 मतदान केंद्र शामिल हैं। जहां पर फिर से शनिवार को वोटिंग होगी।

प्रमुख समाचार

सीएम के बयान पर ढाका ने जताई कड़ी आपत्ति, भेजा समन

नईदिल्ली। हिमंता बिस्वा सरमा के बयान से भारत-बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते ढाका ने भारतीय राजनयिक को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेश ने इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक बयानबाजी दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों को प्रभावित कर सकती है।

भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक स्तर पर हलचल देखने को मिली है, जहां हालिया बयान को लेकर बांग्लादेश ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए एक बयान के बाद सामने आया है, जिस पर बांग्लादेश ने औपचारिक विरोध जताया है। मौजूद जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बधे को तलब किया और उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की। यह बैठक 30 अप्रैल 2026 को ढाका में हुई, जहां दक्षिण एशिया प्रभाग की महानिदेशक इशरत जहां ने बांग्लादेश का पक्ष भारतीय राजनयिक के सामने रखा है।

विवादित बयान पर राहुल इलाहाबाद कोर्ट को से मिली राहत

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक पुराने बयान से जुड़ा था, जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने

अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पहले ही इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और 8 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।यह विवाद राहुल गांधी के उस बयान से शुरू हुआ था जो उन्होंने 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान दिया था। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ है। उन्होंने पहले संभल की निचली अदालत में शिकायत की थी, लेकिन वहां से अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही माना और याचिका को कमजोर बताते हुए रद्द कर दिया।

पंजाब में सरकारी इमारत पर लहराया गया खालिस्तानी झंडा

नईदिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की एक विशेष अदालत ने देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साल 2020 में पंजाब के मोगा स्थित उपायुक्त कार्यालय पर खालिस्तानी झंडा फहराने के जुर्म में दो आरोपियों को पांच साल छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है।एनआईए ने एक बयान में कहा कि मोहाली के एसएएस नगर में स्थित अदालत ने मोगा के निवासी आरोपियों इंदरजीत सिंह और जसपाल सिंह को पांच साल छह महीने की सजा सुनाई और 16-16 हजार रुपये जुर्माना लगाया। एनआईए ने इससे पहले इन दोनों के साथ गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों और अमेरिका में रहने वाले दो फरार आरोपियों पन्नू व उसके सहयोगी राणा सिंह उर्फ हरप्रीत सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मोहाली की विशेष अदालत ने 2021 में पन्नू और हरप्रीत को इस मामले में भगोड़ा घोषित किया था। इंदरजीत और जसपाल ने 14 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मोगा के उपायुक्त कार्यालय पर खालिस्तानी झंडा फहराया था।

सीएम भगवंत पर नशे में विधानसभा पहुंचने का लगा आरोप

नईदिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गए हैं। आज विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह कथित रूप से नशे की हालत में सदन में पहुंचे। इस आरोप ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है और सत्ता तथा

विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों का तुरंत अल्कोमीटर और डोप परीक्षण कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। बाजवा का कहना है कि यदि इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच जरूरी है। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने भी इस मामले को और हवा दे दी। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री नशे की हालत में विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को तुरंत शराब जांच से गुजरना चाहिए और यदि आरोप सही साबित होते हैं ।

तेजस प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड रवि कुमार बने हेल के नए सीएमडी

नई दिल्ली। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (हेल) को नया नेतृत्व मिल गया है। तेजस प्रोजेक्ट से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी रवि कुमार ने शुक्रवार को कंपनी के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने डॉ. डीके सुनील का स्थान लिया है,

जो 30 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त हुए।रवि कुमार के पास अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इससे पहले वे हेल में निदेशक (संचालन) के पद पर कार्यरत थे और कंपनी को 'महारत्न' का दर्जा दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। पदभार ग्रहण करने के बाद रवि कुमार ने कहा कि उनका लक्ष्य हेल को नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परिचालन उत्कृष्टता के आधार पर एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एयरोस्पेस और रक्षा उद्यम बनाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कर्मचारियों की भागीदारी और तकनीकी उन्नयन कंपनी की भविष्य की रणनीति का प्रमुख हिस्सा होंगे।

पश्चिम बंगाल में खेला होबे बनाम परिवर्तन होबे

किशन भावनानीं

वैश्विक स्तरपर पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक राजनीति,संघीय ढांचे,वैचारिक संघर्ष और चुनावी रणनीतियों का एक ऐसा प्रयोगशाला बन चुका है जिस पर पूरे देश ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक विश्लेषकों की भी पैनी नजर टिकी हुई है। जब मतदान के दोनों चरण अभूतपूर्व उत्साह और अत्यधिक मतदान प्रतिशत के साथ संपन्न हुए,तो यह अपने आप में कई संकेत देता है,पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ 4 मई का जब नतीजे आएंगे और क्लियर हो जाएगा कि सत्ता में ममता बनर्जी की वापसी होगी या फिर इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, वह कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जमीन हिला रहे हैं। तमाम टीएमसी नेताओं की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। और कुछ नेता तो क्या कह रहे हैं टीएमसी के?

टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी हर बार इस तरीके का माहौल बनाती है और उसका माहौल उल्टा ही साबित होता है। इस बार जो बंगाल में 200 पार का यह लोग बातें कर रहे हैं। इस बार वो बातें हवा-हवाई ही साबित होंगी क्योंकि 4 मई को जो नतीजे आएंगे वो टीएमसी के पक्ष में आएंगे। हालांकि बीजेपी वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी के साथ खेला होगा। एक तरफ जनता की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी, दूसरी तरफ सत्ता के प्रति गहरी असंतुष्टि या समर्थन का तीव्र भाव। पश्चिम बंगाल में 92 प्रतिशत से अधिक मतदान कोई साधारण घटना नहीं है;यह दर्शाता है कि चुनाव केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता के लिए निर्णायक क्षण बन चुका है। मैं यह मानता हूं कि इस पृष्ठभूमि में बदला बनाम बदलाव की बहस,वोटों की बरसात और सत्ता परिवर्तन जैसे सवाल

केवल नारे नहीं बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान के संकेतक बन जाते हैं।अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो पश्चिम बंगाल लंबे समय तक वैचारिक राजनीति का केंद्र रहा है। वामपंथी शासन के तीन दशक और उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का उदय, ये दोनों ही चरण बताते हैं कि बंगाल की राजनीति हमेशा परिवर्तनशील रही है।लेकिन वर्तमान चुनाव में जो सबसे बड़ा बदलाव दिखता है,वह है बीजेपी का अभूतपूर्व उभार,जिसने राज्य की पारंपरिक द्विध्रुवीय राजनीति को त्रिकोणीय और अब लगभग द्विध्रुवीय संघर्ष में बदल दिया है।

साथियों बात अगर हम भारत भारत व पूरे विश्व की नजरों में अब पहले सबसे बड़े प्रश्न की करें,पूरी दुनिया की नजरें सोमवार 4 मई 2026 के नतीजों पर क्यों टिकी हैं? इसका उत्तर केवल सीटों के गणित में नहीं बल्कि उस राजनीतिक कथा में छिपा है जो भारत के लोकतंत्र को परिभाषित करती है। बंगाल का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि क्या क्षेत्रीय दल अभी भी अपने मजबूत गढ़ों को बचा सकते हैं या राष्ट्रीय दलों का विस्तार अब लगभग हर राज्य में संभव हो गया है। यह चुनाव पीएम के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय राजनीति बनाम क्षेत्रीय पहचान की राजनीति का सीधा मुकाबला भी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे लोकल बनाम नेशनल नैरेटिव के रूप में देखा जा रहा है, जो कई लोकतांत्रिक देशों में उभरती प्रवृत्ति से मेल खाता है।साथियों बात अगर हम बदला या बदलाव,इस प्रश्न को समझने की करें तो पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे संवेदनशील पहलू को छूता है। बदला शब्द बंगाल में राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध की उस संस्कृति की ओर इशारा करता है जो दशकों से चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा रही है। वहीं बदलाव विकास, प्रशासनिक सुधार और नई राजनीतिक दिशा का प्रतीक है। इस चुनाव में दिलचस्प बात यह रही कि व्यापक रूप से हिंसा की घटनाएं अपेक्षाकृत कम देखने को मिलीं,जिसका श्रेय केंद्रीय बलों की तैनाती और कड़ी निगरानी को दिया जा रहा है। यह बदलाव केवल चुनावी प्रक्रिया में नहीं बल्कि मतदाताओं के मनोविज्ञान में भी झलकता है,वे अब स्थिरता और सुरक्षा को सटीकता से प्राथमिकता दे रहे हैं।

बिलासपुर में कारोबारी के ठिकानों ईडी का छापा

17 किलो सोना और तीन करोड़ के हीरों का हार जब्त

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई तेज हो गई है। ईडी की टीम ने गुरुवार को बिलासपुर में सराफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर और दुकान पर दबिश दी। सूत्रों के अनुसार, दिनभर चली इस छापेमारी कार्रवाई में टीम को भारी मात्रा में कीमती सामान बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि छापे के दौरान करीब 17 किलो सोना, करीब 3 करोड़ रुपये के हीरों के हार और बड़ी मात्रा में नकदी मिली है।

जानकारी के मुताबिक, विवेक अग्रवाल फरार चल रहे वांटेड आरोपी विकास अग्रवाल के भाई हैं। विकास अग्रवाल को इस मामले में अहम कड़ी माना जा रहा है और वह मुख्य आरोपी अनवर ढेबर का करीबी बताया जाता है। ईडी की यह कार्रवाई शराब घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल एजेंसी पूरे मामले में बरामद दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ईडी की टीम गुरुवार तड़के विवेक अग्रवाल के मैग्नेटो मॉल के पीछे स्थित घर पर पहुंची। अचानक हुई इस कार्रवाई से किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। अधिकारियों ने घर के सभी एंट्री गेट को सील कर दिया और सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया। घर के अंदर दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की गहन जांच चलती रही। वहीं, दूसरी टीम विवेक अग्रवाल के सदर बाजार स्थित श्रीराम ज्वेलर्स भी पहुंची। टीम यहां दुकान के स्टॉक, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच करती रही। शराब घोटाले का सिंडिकेट बनाने वाले कारोबारी अनवर ढेबर ने अपने बेहद करीबी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को भी सिंडिकेट में शामिल किया था। कमीशन के इन पैसों को अनवर विकास अग्रवाल और उसके भाई विवेक अग्रवाल की मदद से लेता था।

कांग्रेस ने कहा- 5 लाख महिलाओं का नाम काटने की साजिश

■ दुर्ग में कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए महतारी वंदन योजना को महतारी दर-बदर योजना बताया. कहा कि केवायसी के नाम पर सरकार परेशान कर रही.

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत अनिवार्य द्र-चङ्घष्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसे महिलाओं को परेशान करने वाला फैसला बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।दुर्ग और भिलाई समेत कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और योजना की प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

कांग्रेस का आरोप है कि द्र-चङ्घष्ट के नाम पर सरकार बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं के नाम योजना से हटा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि करीब 5 लाख महिलाओं को इस प्रक्रिया के जरिए लाभ से वंचित किया जा रहा है, जो सीधा-सीधा गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के साथ अन्याय है।भिलाई में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनसमस्याओं के साथ-साथ महतारी वंदन योजना की अव्यवस्था को भी प्रमुख मुद्दा बनाया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि योजना का लाभ देने में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और महिलाओं को बार-बार दस्तावेज़ और द्र-चङ्घष्ट के नाम पर परेशान किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता सौरभ मिश्रा ने यह भी दावा किया कि हर महीने 600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि योजना में खर्च होने के कारण सरकार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। इसी वजह से सरकार अब बहाने बनाकर लाभार्थियों की संख्या कम करने की कोशिश कर रही है।

इस प्रदर्शन में विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र परगनिया, पार्षद सुरेश वर्मा, हरीश सिंह, राजेश चौधरी, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष ख्वाजा अहमद समेत कई कांग्रेस नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या सफाई देती है और क्या द्र-चङ्घष्ट प्रक्रिया में किसी तरह की राहत दी जाती है या नहीं।

पार्षद ने महिला के मुख्य द्वार में लगाया ताला

जगदलपुर। निगम क्षेत्र अंतर्गत शहीद गुंडाधुर वार्ड क्रमांक 45 में एक विधवा महिला नजूल भूमि पर स्थित अपने घर में निर्माण कार्य को लेकर गंभीर विवाद में फंस गई है। पीड़िता महिला श्रीमती बालो कश्यप (55 वर्ष), निवासी जोरीपारा, ने प्रेसवार्ता में बताया कि वह करीब 45 वर्षों से यहां पर निवासरत है, पति के निधन के बाद वह मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही हैं। उनके पांच बेटियां हैं और कोई पुत्र नहीं है।

जर्जर कच्चे मकान को तोड़कर नया घर बनाने के लिए मैने नगर निगम से अनुमति लेकर निर्माण कार्य शुरू किया था। किन्तु निर्माण कार्य के दौरान विवाद उत्पन्न हुआ और घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जिससे पूरा कार्य रुक गया। इस संबंध में बोधघाट थाना में 23 अप्रैल को शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रेसवार्ता के दौरान श्रीमती बालो कश्यप ने आरोप लगाया कि वार्ड क्रमांक 45 की पार्षद गायत्री बघेल द्वारा दोबारा गेट में ताला लगा दिया गया, जिससे वह अपने ही घर में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। इस वजह से उन्हें अपनी बेटियों के साथ दर-दर भटकने की नौबत आ गई है। पीड़िता ने बताया कि बार-बार निवेदन करने के बावजूद न तो ताला हटाया गया और न ही कोई समाधान निकाला गया। मजबूरी में एक बार ताला तोड़कर निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन पुनः ताला जड़ दिया गया। महिला ने नगर निगम आयुक्त, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

ग्राम स्तर पर जन-जागरूकता से रोका जा सकता है, बाल विवाह

जगदलपुर। बस्तर जिले के ग्राम पंचायत पोड़ागुड़ा में बस्तर सामाजिक जन विकास समिति द्वारा शुक्रवार को संचालित चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्लस्टर स्तर पर ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम संस्था के सचिव डॉ. सुशील कुमार पाण्डेय के निर्देशन में जगदलपुर विकासखंड के 12 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को बाल संरक्षण, बाल अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम, मानव तस्करी, नशा मुक्ति तथा बाल विवाह रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण तंत्र को सशक्त बनाने, समुदाय में जागरूकता बढ़ाने तथा बच्चों के सुरक्षित एवं उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। प्रशिक्षण सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में बाल कल्याण समिति बस्तर के अध्यक्ष नरेंद्र पाणिग्राही एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी डॉ. विजय शंकर शर्मा उपस्थित रहे।

इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र पाणिग्राही ने बच्चों के अधिकारों एवं बाल विवाह की रोकथाम में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ग्राम स्तर पर सक्रिय निगरानी और जन-जागरूकता से बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंचायतें न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सहित चारों आरोपियों की याचिका खारिज

■ दंतेवाड़ा में ही चलेगा ट्रायल

जगदलपुर। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके की आपराधिक स्थानांतरण याचिका (टीपीसीआर नंबर 07/2026) को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया है कि मामले का ट्रायल दंतेवाड़ा की जिला एवं सत्र अदालत में ही जारी रहेगा। आरोपी सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को दंतेवाड़ा से जगदलपुर स्थानांतरित करने की मांग की थी। आरोपियों के वकील ने दलील दी कि जगदलपुर जेल से दंतेवाड़ा कोर्ट तक लगभग 80 किलोमीटर के रास्ते में उनकी जान को खतरा है। इसी आधार पर ट्रायल स्थान बदलने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने आरोपियों के तर्कों को खारिज करते हुए अदालत को बताया कि पेशी में कोई सुरक्षा या लाजिस्टिक दिक्कत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की व्यवस्था उपलब्ध है। आवश्यकता होने पर आरोपियों को दंतेवाड़ा जेल शिफ्ट किया जा सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा का हवाला देकर ट्रायल की प्रक्रिया और स्थान को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में सभी आरोपियों को 4 मई को दंतेवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा।

उल्लेखनीय हैं कि स्वतंत्र पत्रकार और बस्तर जंक्शन यूट्यूब चैनल के संचालक मुकेश चंद्राकर की एक जनवरी 2025 को निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। उनका शव पत्रकार मुकेश के ही चचेरे भाई ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के घर के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। आरोप है कि मुकेश ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खुलासा किया था, जिसके चलते रंजिश में इस हत्या को अंजाम दिया गया।

वनभूमि पर कब्जा, पेड़ों की कटाई और दावा 'प्रकृति प्रेमी' होने का

गरियाबंद। जिस डिजिटल साक्ष्य के सहारे उदंती सीतानदी अभयारण्य प्रशासन 510 करोड़ की 850 हेक्टेयर भूमि से अवैध कब्जा हटाने में सफल हुआ था, अब उसे अतिक्रमणकारी चुनौती दे रहे हैं। 265 एकड़ में फैले हजारों पेड़ों की अवैध कटाई के बाद अतिक्रमण करने वाले 166 आरोपियों ने लिखित जवाब में कहा हम प्रकृति प्रेमी, पुरखों के द्वारा काबिज जमीन पर काश्तकारी करते आ रहे हैं। हमने अभयारण्य क्षेत्र में कोई नियम नहीं तोड़ा है। उदंती सीतानदी अभयारण्य के सीतानदी रेंज में जैतपुरी से लगे इलाके में विगत 15 वर्षों में हजारों पेड़ों की कटाई कर 265 एकड़ वन भूमि पर काबिज आरोपी आज एकसाथ उदंती सीतानदी अभयारण्य के गरियाबंद स्थित दफ्तर पहुंचे। आरोपियों ने अपने लिखित जवाब में अवैध कब्जा के आरोप को खारिज कर डिजिटल साक्ष्य को नकारने की कोशिश की। अतिक्रमणकारियों की दलील है कि गृह ग्राम जैतपुरी से लगे कक्ष क्रमांक 324 उनके निजी भूमि क्षेत्र के सीमा में आता है। अपने आप को प्रकृति प्रेमी बताते हुए कहा कि काबिज उनके पूर्वजों ने किया, उनके द्वारा दी गई काबिज भूमि पर ही वे काश्तकारी कर रहे हैं। आगे लिखा है कि कक्ष क्रमांक में हमेशा सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, ऐसे में उनके द्वारा कोई कटाई-सफाई नहीं किया गया है। वहीं उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि जो सेटेलाइट इमेज हमारे पास मौजूद है। उसके हिसाब से सारे पेड़ 2008 के बाद काटे गए और अतिक्रमण किया गया। अब कार्रवाई से बचने के लिए पुरखौती जमीन होने की दलील दे रहे हैं। खुद को प्रकृति प्रेमी बता रहे हैं जो मनगढ़ंत है। मामले में उपनिदेशक वरुण जैन ने कहा कि पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की गई है। 2005 के बाद 2010 से 2022 के बीच सारे कटाई हुई है,सेटलाइट से जारी इमेजरी में इसका खुलासा हुआ है। 2011 तक 45 हेक्टेयर में कटाई हुई थी वही 10 साल बाद बढ़ कर 106 हेक्टेयर हो गया। पेड़ों के ठूठ और जलाए गए अवशेष का पंचनामा कर साक्ष्य जुटाए गए हैं। सभी 166 आरोपियों के विरुद्ध पीओआर क्रमांक 15/10,15/11,15/12 एवं 15/13 दर्ज कर वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सारे सबूतों को न्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जहां सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। 2008 के बाद काबिज लोगों का खुलासा 2022 से होना शुरू हुआ, जब उदंती सीतानदी अभयारण्य में उपनिदेशक बन कर वरुण जैन आए। आईटी एक्सपर्ट जैन उन्होंने ने 2023 में गूगल अर्थ की मदद से अभ्यारण का रिमोट सेंसिंग पोर्टल तैयार किया। इस पोर्टल में 20 साल से भी ज्यादा पुराना सैटेलाइट इमेजेस मौजूद है। 2006,2008,2010 में ली गई तस्वीरों के अध्ययन से अवैध कटाई और कब्जो का खुलासा होते गए। हालिया, कार्रवाई से पहले वरुण जैन ने घोरागांव, सोरमाल, बुढ़गेलटप्पा, बनवापारा, गरीबा, कोकड़ी, गोना, कांडसर, फरसरा, पीपलखुटा, कारिपानी, करलाझर नागेश इलाके से कुल 850 हेक्टेयर भूमि पर बेदखली की कार्रवाई किया। सभी में डिजिटल साक्ष्य की दलील मजबूती से कार्रवाई का ढाल बना रहा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

देवभोग में फिर 36 घंटे में तीसरी बार भूकंप के झटके

गरियाबंद। देवभोग क्षेत्र में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज दोपहर करीब 2:20 बजे धरती हल्की कांपी, जिससे इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। लगातार आ रहे झटकों से ग्रामीणों में चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं गरियाबंद जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, पिछले 36 घंटों के भीतर यह तीसरी बार है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले बीती रात 7:20 बजे भी धरती कांपी थी। वहीं एक दिन पहले आए झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 0.7 दर्ज की गई थी। हालांकि झटके हल्के बताए जा रहे हैं और अभी तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन बार-बार हो रही इस गतिविधि ने लोगों को डरा दिया है। कई ग्रामीण एहतियातन घरों से बाहर निकल आए और खुले स्थानों पर समय बिताते नजर आए। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, हल्के झटके भूगर्भीय हलचल का संकेत हो सकते हैं।

युवती से फोन पर बात करने पर परिजन ने की पिटाई

सूरजपुर। जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को घर बुलाकर कुर्सी पर बैठाया गया और फिर बेल्ट से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस भी मामले में संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। यह घटना जयनगर थाना क्षेत्र के सिलफिली मदनपुर की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, मार खाने वाला युवक मैनपाट का रहने वाला है। केनापारा में किराए के मकान में रहकर ड्राइवर का काम करता था। बताया जा रहा है कि युवक को किसी माध्यम से एक युवती का मोबाइल नंबर मिला, जिसके बाद वह उससे फोन पर बातचीत करने लगा। जब इस बात की जानकारी युवती के परिजनों को हुई, तो उन्होंने इसका विरोध किया।आरोप है कि युवती के भाई ने युवक को फोन कर अपने घर बुलाया। जैसे ही युवक वहां पहुंचा, उसे जबरन कुर्सी पर बैठाया गया और बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई की गई। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है।

इया आपलो सामान निया, अभियान पर लौटाए 141 गुम मोबाइल

दंतेवाड़ा। 'इया आपलो सामान निया' अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस ने आम जनता के गुम हुए मोबाइल और संपत्ति को वापस लौटाया बया है। इस विशेष अभियान के जरिए कुल 141 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे गए, जिनकी अनुमानित कीमत 31 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार वर्मन और साइबर सेल नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक ठाकुर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से न सिर्फ जिले बल्कि उत्तरप्रदेश और आस-पास के जिलों जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर व कोंडागांव से भी गुम मोबाइल बरामद किए। दंतेवाड़ा पुलिस ने नागरिकों की सुविधा के लिए सायबर हेल्पलाइन नंबर 9479151665 जारी किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार की हेल्पलाइन 1930 और ईमेल cyber-crime@gov.in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच गरियाबंद में गिरे ओले

गरियाबंद। पूरे छत्तीसगढ़ में जहां भीषण गर्मी है वहीं गरियाबंद जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदला और भारी ओलावृष्टि हुई है। जिले के इंदागांव, उदंती और जुगाड़ क्षेत्र में जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे। ओलों की वजह से नेशनल हाईवे 130C का इंदागांव से जुगाड़ तक का हिस्सा सफेद रंग में रंग गया। लगातार बढ़ रही गर्मी से परेशान लोगों को भी इस ओलावृष्टि और बारिश से बड़ी राहत मिली है। कल भी इन क्षेत्रों में बारिश हुई थी, जिसके बाद आज फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। बारिश और ओले गिरने से मौसम सुहावना हो गया है। भले ही मौसम सुहाना हुआ हो लेकिन मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक मौसम परिवर्तन के कारण मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। मवेशियों को चोट लगने का भी खतरा होता है। इसके अलावा बागवानी की फसलों को भी नुकसान होता है। बीमारियों के खतरे के साथ ही भारी बारिश और ओलावृष्टि से हरा सोना यानी तेंदूपत्ता को भारी नुकसान हुआ है।

35 लाख की फायर ब्रिगेड गायब, फाइल भी लापता

खैरागढ़। नगर पालिका खैरागढ़ में 35 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई फायर ब्रिगेड वाहन पिछले कई वर्षों से लापता है। हैरानी की बात यह है कि वाहन का ठिकाना तो दूर, उससे जुड़ी खरीद फाइल भी पहले गायब हो चुकी है। इस मामले में नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, जिससे पूरे प्रकरण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार, अविभाजित राजनांदगांव जिले के दौरान गौण खनिज मद से नगर पालिका को दो किश्तों में लगभग 35 लाख रुपये जारी किए गए थे। पहली किश्त में 13 लाख 13 हजार रुपये से वाहन का चेसिस खरीदा गया, जबकि दूसरी किश्त में 21 लाख रुपये से अधिक खर्च कर वाहन को पूर्ण रूप से तैयार कराया गया। अक्टूबर 2020 में यह वाहन नगर पालिका को सौंपा गया था। कुछ महीनों तक सेवा देने के बाद वाहन अमलीडीह के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद उसे मरम्मत के लिए भेजा गया। इसके बाद से यह वाहन आज तक शहर वापस नहीं लौटा।

छत्तीसगढ़ के इकलौते आवासीय नेत्रहीन विद्यालय का शत प्रतिशत रिजल्ट

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। छत्तीसगढ़ 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में मनेन्द्रगढ़ स्थित नेत्रहीन विकलांग शिक्षण एवं प्रशिक्षण विद्यालय के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. विद्यालय में अध्ययनरत सभी 16 नेत्रहीन दिव्यांग छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम आने से विद्यालय परिवार में खुशी और गर्व का माहौल है। जानकारी के अनुसार विद्यालय में रहकर 12वीं कक्षा के 7 तथा 10वीं कक्षा के 9 विद्यार्थी ब्रेल लिपि के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे। कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इनमें से कुल 9 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें 12वीं के 5 और 10वीं के 4 छात्र शामिल हैं। विद्यालय प्रबंधन के मुताबिक नेत्रहीन बच्चों के लिए पढ़ाई आसान नहीं होती, लेकिन शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन, विशेष शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों की मेहनत ने यह संभव कर दिखाया।

परिणाम घोषित होते ही विद्यालय परिसर में उत्साह का माहौल बन गया। विद्यार्थियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की।सफल विद्यार्थियों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों और अभिभावकों को दिया।छात्रों ने कहा कि विद्यालय में उन्हें न केवल शिक्षा दी गई, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी मिली, जिसके कारण वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। नेत्रहीन विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर सामाजिक संस्था आम नागरिक मंच से जुड़े लोग भी विद्यालय पहुंचे।उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं। संस्था के सदस्यों ने कहा कि इन बच्चों की सफलता समाज के लिए प्रेरणादायी है और यह साबित करती है कि यदि अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो दिव्यांगजन भी किसी से कम नहीं हैं। गौरतलब है कि मनेन्द्रगढ़ का विद्यालय छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा आवासीय नेत्रहीन विद्यालय है, जहां केवल दृष्टिबाधित बच्चे रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। वर्षों से यह संस्था दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षित कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कर रही है।इस वर्ष का शानदार परीक्षा परिणाम विद्यालय की गुणवत्ता और शिक्षकों की मेहनत को दर्शाता है। विद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है, ताकि दिव्यांग बच्चे आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित कर सकें।

भिलाई में सरकारी नौकरी के नाम पर 16 लाख की ठगी

दुर्ग। जिले के भिलाई में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से लाखों रुपये की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी सातुम सेम्युल गुज्जर उर्फ आदी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बकायदा फर्जी नियुक्ति पत्र भी बांटा था।

आरोपी खुद को बड़े रसूख वाला व्यक्ति बताता था। उसने ठगी करने के लिए बहुत ही शातिर तरीका अपनाया। वह नौकरी के नाम पर लोगों से रायपुर मंत्रालय और भिलाई के मशहूर कॉफी हाउस में मिलता था, ताकि किसी को उस पर शक न हो। आरोपी ने उपासना देशमुख समेत चार लोगों को शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बीएसपी में नौकरी लगाने का झांसा दिया। भरोसा जीतने के लिए उसने पीड़ितों को बाकायदा %जॉइनिंग लेटर% भी दिए, जो पूरी तरह फर्जी थे। इसके बदले उसने पीड़ितों से कुल 16 लाख 15 हजार रुपये वसूले। जब पीड़िता उपासना देशमुख अपना जॉइनिंग लेटर लेकर काम पर पहुँची, तब उसे पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। भिलाई नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद हुए हैं। उस पर जालसाजी और धोखाधड़ी की धाराओं (420, 467, 468) के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह में कुछ और लोग भी शामिल हैं।

केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें, भर्तियों की जानकारी हमेशा संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या शिक्षा विभाग का आधिकारिक पोर्टल पर ही देखें। व्हाट्सएप या किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए विज्ञापन को सच न मानें।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस के बोरे-बासी दिवस पर सीएम साय का तंज, कहा- रोज बोरे-बासी खाते हैं

रायपुर। कांग्रेस के शुक्रवार को बोरे-बासी दिवस मनाए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बोरे-बासी दिवस मनाने का जरूरत ही नहीं है। गांव में तो लोग रोज बोरे-बासी खाते हैं। ऐसा करके ये लोग खुद को ज्यादा छत्तीसगढ़िया दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रदेश में शुक्रवार से साय सरकार का सुशासन तिहार शुरू हो गया है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि 10 जून तक सुशासन तिहार मनाया जाएगा। इस दौरान जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाए जाएंगे। हम स्वयं और जनप्रतिनिधि शिविर में शामिल होंगे।

'गूगल बॉय' रुद्र को, लोक भवन में मिला सम्मान

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से शुक्रवार को लोक भवन में जिला दुर्ग के 6 वर्षीय गूगल बॉय रुद्र शर्मा ने अपने पालकों के साथ मुलाकात की। अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति से उसने हैरान कर दिया। राज्यपाल श्री डेका से मुलाकात के दौरान रुद्र ने सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सवालों के सटीक उत्तर देकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कक्षा पहली के छात्र रुद्र को यूपीएससी और पीएससी स्तर के प्रश्नों के उत्तर भी याद हैं। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उससे छत्तीसगढ़ के गठन, राज्य की विशेषताओं और भारतीय संविधान से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका रुद्र ने बिना झिझक तुरंत सही जवाब दिया। रुद्र की तेज स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर राज्यपाल ने उसकी सराहना की। उन्होंने लोक भवन की ओर से रुद्र को प्रमाण पत्र प्रदान किया और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर रुद्र के माता श्रीमती पायल शर्मा के साथ उसके नाना श्री विनोद शर्मा भी उपस्थित थे, जिन्होंने उसकी उपलब्धि पर खुशी जाहिर की।

रायपुर कला केंद्र में समर कैंप का भव्य शुभारंभ, 135 से अधिक बच्चों की भागीदारी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की परिकल्पना तथा कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कला केंद्र रायपुर में 15 दिवसीय समर कैंप के प्रथम बैच का भव्य शुभारंभ किया गया। कैंप के पहले ही दिन बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतिभागियों ने रंग-बिरंगी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए नई-नई विधाओं को सीखने की शुरुआत की। समर कैंप के अंतर्गत बच्चों को गायन, वादन, गिटार, कीबोर्ड, नृत्य, क्ले आर्ट, पेंटिंग, माटी कला तथा ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह समर कैंप तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है,1से 15 मई, 16 मई से 30 मई तथा 1 जून से 15 जून तक। अब तक 135 से अधिक बच्चों का पंजीयन हो चुका है, जो इस पहल के प्रति बच्चों और अभिभावकों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। कैंप का समय प्रात: 7:30 बजे से 9:30 बजे तक निर्धारित है। प्रारंभिक 30 मिनट में योग और जुंबा कराया जा रहा है, जबकि शेष समय में बच्चों को उनकी रुचि अनुसार विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कला केंद्र के नोडल अधिकारी श्री केदार पटेल ने बताया कि समर कैंप एवं कला केंद्र से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभिभावक 9109029034 एवं 9669039034 पर संपर्क कर सकते हैं।

सुशासन तिहार बना दिखावा, जनता के हजारों आवेदन ठंडे बस्ते में : आप

रायपुर। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवलाल नरेटी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य सरकार के 1 मई से 10 जून 2026 तक प्रस्तावित सुशासन तिहार को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। पिछले साल भी सरकार ने सुशासन त्यौहार मनाया था और इसी महीने सरकार ने 1 से 15 अप्रैल तक प्रदेश के हर जिले में समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाए, लेकिन इन शिविरों में आम जनता द्वारा दिए गए हजारों आवेदन आज तक लंबित पड़े हैं। सरकार जवाब दे कि पिछले साल सुशासन तिहार में प्रदेश से कुल कितने आवेदन आये और कितने आवेदनों का निराकरण हुआ? साय सरकार निठल्ली सरकार है जनता की तकलीफों से इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। देवलाल नरेटी ने आरोप लगाया कि सरकार ने बड़े-बड़े दावे कर जनता को राहत देने की बात कही थी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। उन्होंने कहा कि लोग अपनी मूलभूत समस्याओं—पानी, बिजली, सड़क, राशन और पेंशन जैसी जरूरी मांगों को लेकर शिविरों में पहुंचे थे, उम्मीद थी कि तत्काल समाधान मिलेगा, लेकिन अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा, सरकार सिर्फ प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट में लगी है। सुशासन तिहार के नाम पर जनता को भ्रमित किया गया।

आम जनता से शालीनता से पेश आएं अधिकारी : मुख्यमंत्री साय

लोगों की सुनें, लोगों को सुनाएं नहीं - मुख्यमंत्री का अधिकारियों को दो टूक निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रशासनिक व्यवस्था को जनकेंद्रित और संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से शासकीय अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए हैं कि वे आमजन के साथ शालीनता, धैर्य और सम्मान के साथ व्यवहार करें। उन्होंने दो टूक कहा कि मुख्यालय और फील्ड स्तर पर शासकीय अधिकारी ही शासन का चेहरा होते हैं, इसलिए उनका आचरण शासन की छवि को प्रभावित करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सुनना प्रशासनिक अधिकारियों का पहला कर्तव्य है। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि वे जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और समाधान पर केंद्रित रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि संवाद तभी सार्थक है, जब उसमें संवेदना और समस्याओं का समाधान करने की नीयत हो।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागों में जनसमस्याओं के निराकरण को प्रभावी, सरल और भरोसेमंद बनाया जाए। जब कोई आम नागरिक किसी शासकीय कार्यालय पहुंचे, तो उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जा रही है और उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सकारात्मक अनुभव ही जनता के मन में विश्वास पैदा करता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि योजनाओं की सफलता केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों के अनुभव से मापी जाती है। इसलिए अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहें, लोगों से सीधे संवाद करें और उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता और तत्परता ही प्रशासन की असली ताकत है।

उन्होंने अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही को अपने कार्य का मूल आधार बनाने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी के साथ-साथ व्यवहार में शालीनता और विनम्रता भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुशासन केवल नीतियों से नहीं, बल्कि व्यवहार से स्थापित होता है। यदि अधिकारी जनता के साथ सरल, सहज, सहयोगात्मक और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण का तरीका हर समय अपनाते हैं, तो प्रशासन स्वयमेव अधिक प्रभावी हो जाता है और शिकायतों की संख्या स्वत: कम होने लगती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का सपना तभी साकार होगा, जब प्रशासन हर नागरिक के लिए सुलभ, संवेदनशील और सम्मानजनक बने। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे इस भावना को अपने कार्य का मूल मंत्र बनाकर आगे बढ़ें और हर व्यक्ति को यह अहसास दिलाएं कि सरकार उसके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि सुशासन तिहार के दौरान वे स्वयं विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के कार्य के साथ-साथ उनके व्यवहार पक्ष का भी अवलोकन करेंगे।उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के दौरान अधिकारियों की संवेदनशीलता, शालीनता और जवाबदेही को प्राथमिकता के साथ परखा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए सुशासन तिहार 2026 का आयोजन 1 मई से 10 जून तक प्रदेशभर में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर समाधान शिविर लगाए जाएंगे।इस दौरान पंचायत एवं वार्ड स्तर पर शिविरों में आवेदन स्वीकार कर जनसमस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सुशासन तिहार में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रहेगी तथा स्वयं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा औचक निरीक्षण और जनसमस्याओं के निराकरण और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।

मातृशक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण हेतु विशेष सत्र

एक तिहाई आरक्षण के संकल्प को मिला व्यापक समर्थन

■ **विष्णुदेव साय ने विशेष सत्र आयोजित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के प्रति किया आभार प्रकट**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा है कि मातृशक्ति उनके लिए केवल सम्मान का विषय नहीं, बल्कि सृजन, संस्कार और सामर्थ्य की आधारशिला है। इसी भावना के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें संसद एवं देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने के संकल्प पर व्यापक चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की जो मजबूत नींव रखी गई है, उसी क्रम में उनकी राजनीतिक भागीदारी को भी सशक्त करना हमारा अगला महत्वपूर्ण कदम है। यह संकल्प देश की आधी आबादी को उनके अधिकारों से पूर्ण रूप से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण विषय पर विशेष सत्र आयोजित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में सदैव याद रखी जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस विशेष सत्र में समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से आई महिलाओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने इस ऐतिहासिक पहल के समर्थन में अपने विचार रखे और महिलाओं के अधिकारों तथा उनके सशक्तिकरण के लिए सशक्त स्वर प्रदान किया। सदन में वरिष्ठ विधायकों और महिला नेतृत्व ने भी पूरे मनोयोग से चर्चा में भाग लेते हुए अपने विचार साझा किए और इस महत्वपूर्ण संकल्प का समर्थन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट रूप से कहा कि नारी शक्ति के सम्मान और अधिकारों के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना न्यायसंगत नहीं है। यह विषय किसी दल या राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के समग्र विकास और उज्ज्वल भविष्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस दिशा में हर सकारात्मक पहल का समर्थन आवश्यक है।

उप मुख्यमंत्री ने दी श्रमिक दिवस की बधाई

कांग्रेस के बोरे बासी दिवस और बैठक पर साव ने साधा निशाना

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का श्रमिक दिवस और सुशासन तिहार को लेकर बयान सामने आया है। अरुण साव ने श्रमिक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण मिले इसके लिए सरकार काम कर रही है। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस के बोरे बासी दिवस, कांग्रेस की बैठक और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के दौरे को लेकर निशाना भी साधा है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रमिकों के पसीने से विकसीत भारत का निर्माण हो रहा है। श्रम कानूनों में परिवर्तन कर सरकार उनके हित में काम कर रही हैं। श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण मिले इसके लिए सरकार काम कर रही है।

सुशासन तिहार को लेकर अरुण साव ने कहा कि आज से 10 जून तक सुशासन तिहार का आयोजन होने जा रहा है। निचले स्तर के अधिकारी से लेकर प्रदेश के मुखिया लोगों से मिलेंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत भी जानेंगे। लोगों को किस तरह से लाभ मिल रहा है इसकी जानकारी लेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के हित में काम कर रहे हैं। सरकार आपके गांव तक पहुंच रही है। अपनी समस्या जरुर बताएं ताकि छत्तीसगढ़ विकसीत हो।

अरुण साव ने कांग्रेस के बोरे बासी अभियान को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिखावे की राजनीति की आदी रही है। बोरे बासी के घोटाले को जनता भूली नहीं। ये लोग काटा चम्मच से बोरे बासी खा रहे थे। प्रदेश के लोग नियमित रूप से बोरे बासी खाते हैं। यह कोई एक दिन का त्यौहार नहीं है। छत्तीसगढ़िया लोगों को बोरे बासी खिलाने का नाटक कांग्रेस बंद करे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं के अभियान का हश्र जनता ने देखा है। सभी राजनीतिक दलों को गतिविधि का अधिकार है। कांग्रेस जनहित और जनता से दूर जा चुकी है। कांग्रेस को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा।

इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सचिन पायलट के दौरे को लेकर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जनहित और सरोकार नहीं। जनता और देशहित से कोई लेना-देना नहीं है। जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी दूर जा चुके हैं। इसका कोई परिणाम नहीं आने वाला है।

छत्तीसगढ़ सरकार का सुशासन तिहार शुरू

■ **1 मई से 10 जून तक चलेगा अभियान, पहले दिन 14 जिलों में शिविर**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को जल्दी और सीधे तरीके से सुलझाने के लिए शुक्रवार से सुशासन तिहार 2026 की शुरुआत हो गई है। ये अभियान 10 जून तक पूरे प्रदेश में चलेगा। इस दौरान गांव और शहर दोनों जगह बड़े पैमाने पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोग अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। सरकार का फोकस इस बार साफ है, लंबित मामलों को जल्द निपटाना और लोगों को दफ्तरों के चक्कर से राहत देना। इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि लोगों को आसान, पारदर्शी और तेज सेवाएं देना ही प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री सुशासन तिहार के दौरान किसी भी जिले में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे।

पहले चरण में लंबित मामलों के निराकरण पर फोकस

अभियान शुरू होने से पहले ही कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे कि 30 अप्रैल तक लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। इसमें खास तौर पर इन मामलों पर ध्यान रखा जा रहा है। *नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरण *मनरेगा के लंबित मजदूरी भुगतान *हितग्राहीमूलक योजनाओं के बकाया भुगतान *आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र से जुड़े मामले* बिजली, ट्रांसफार्मर और पेयजल (हैंडपंप) की समस्याएंइसके साथ ही पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर दिया गया है* उज्ज्वला योजना * राशन कार्ड *आयुष्मान भारत योजना * सामाजिक सुरक्षा पेंशन *ग्रामीण-शहरी दोनों इलाकों में तय फॉर्मेट में लगेंगे शिविरआज 14 जिलों में समाधान शिविर लगाए गए हैं।

शहरी क्षेत्रों में वार्ड अनुसार शिविर

1 मई से 10 जून के बीच अलग-अलग जगहों पर समाधान शिविर लगाए जाएंगे। गांवों में 15 से 20 पंचायतों को मिलाकर शिविर होंगे, जबकि शहरों में वार्ड के हिसाब से आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में मौके पर ही आवेदन लिए जाएंगे और जहां संभव होगा, वहीं समाधान या लाभ भी दिया जाएगा। कोशिश यह रहेगी कि हर आवेदन का निपटारा एक महीने के भीतर हो जाए। साथ ही लोगों को यह भी बताया जाएगा कि उनका आवेदन किस स्थिति में है। समाधान शिविरों में जनता की समस्याओं को सुलझाया जाएगा।

राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की दोहरी उपलब्धि

फाइलेरिया व मलेरिया नियंत्रण में राज्य मॉडल की देशभर में सराहना

रायपुर। जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। 30 अप्रैल और 01 मई 2026 को चंडीगढ़ में आयोजित नवाचार और समावेशिता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन - भारत के भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम पद्धतियाँ में राज्य को फाइलेरिया और मलेरिया उन्मूलन के लिए अपनाई गई नवाचारी पहलों पर सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल राज्य की स्वास्थ्य रणनीतियों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है, बल्कि सामुदायिक भागीदारी आधारित मॉडल की सफलता का भी प्रमाण है।

फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में बिहान (स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन) से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। मिशन संचालन समूह - मानव संसाधन (एमएसजी-एचआर) के अंतर्गत इस मॉडल को देश की सर्वश्रेष्ठ नवाचारी और समावेशी पहल के रूप में मान्यता

मिली, जिसमें पीसीआई इंडिया का तकनीकी सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के दौरान महिलाओं ने घर-घर पहुंचकर न केवल दवा सेवन सुनिश्चित कराया, बल्कि समुदाय में व्याप्त भ्रांतियों को भी दूर किया। सामुदायिक बैठकों और जागरूकता गतिविधियों के जरिए लोगों में भरोसा कायम किया गया। इसका परिणाम यह रहा कि दवा सेवन से इनकार करने वाले लगभग 74 प्रतिशत लोगों को सहमति के लिए तैयार किया गया-जो इस मॉडल की सबसे बड़ी सफलता के रूप में उभरकर सामने आया।

सम्मेलन में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को भी एक प्रभावी और परिणामोन्मुख पहल के रूप में विशेष सराहना मिली। बस्तर के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में संचालित इस अभियान के तहत घर-घर स्क्रीनिंग, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) से समय पर जांच, त्वरित उपचार और दिन-7 व दिन-14 फॉलो-अप के माध्यम से पूर्ण इलाज सुनिश्चित किया गया। इस अभियान की खास उपलब्धि लक्षणहीन (स्पर्शोन्मुख) मरीजों की पहचान रही, जिससे संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में निर्णायक मदद मिली। इसके सकारात्मक परिणाम भी स्पष्ट रूप से सामने आए हैं- राज्य का एपीआई वर्ष 2019 में 1.97 से घटकर 2025 में 0.90 हो गया, जबकि बस्तर संभाग में यह 13.12 से घटकर 6.98 तक पहुंच गया। राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं ने छत्तीसगढ़ के बिहान आधारित सामुदायिक मॉडल और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया। कम लागत में अधिक प्रभाव देने वाली ये पहलें यह साबित करती हैं कि जनभागीदारी और स्थानीय रणनीतियों के माध्यम से जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान संभव है।

मिशन उत्कर्ष: जिला प्रशासन और अदाणी फाउंडेशन की साझेदारी से रायपुर में बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार

रायपुर। रायपुर जिले में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के शासकीय विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार के उद्देश्य से जिला प्रशासन के नेतृत्व में एवं अदाणी फाउंडेशन के सहयोग से 'मिशन उत्कर्ष' का संचालन किया गया। कार्यक्रम का मार्गदर्शन कलेक्टर ने किया, जबकि समन्वय और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा विभाग ने निभाई।

पूर्व में रायपुर जिले की बोर्ड परीक्षा रैंकिंग लगभग 33वें स्थान के आसपास थी। इसे ध्यान में रखते हुए एक डेटा-केंद्रित शैक्षणिक मॉडल तैयार कर जिले के 215 शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में लागू किया गया। इस पहल के तहत कक्षा 10वीं के लगभग 16,100 और कक्षा 12वीं के लगभग 13,000 विद्यार्थियों को शामिल किया गया। इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के साथ विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थी शामिल रहे।

उल्लेखनीय परिणाम (शैक्षणिक सत्र 2025-26)

कक्षा 10वीं : जिला रैंक: 32 से बढ़कर 27। उत्तीर्ण प्रतिशत: 66.24% से बढ़कर 71.05%। **कक्षा 12वीं :** जिला रैंक: 25 से बढ़कर 15। उत्तीर्ण प्रतिशत: 79.94% से बढ़कर 84.79%

कक्षा 10वीं की टॉप-10 मेरिट सूची में 2 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया, जिनमें अधिकतम अंक 592 (98.67%) रहे। कक्षा 12वीं में टॉप-10 मेरिट सूची में 5 विद्यार्थियों ने स्थान बनाते हुए 96 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किए। कुल मिलाकर लगभग 29,000 विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ यह पहल जिले के शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक स्तर में सुधार की दिशा में एक संगठित प्रयास के रूप में सामने आई है।

कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

//अधिसूचना//

गरियाबंद दिनांक 02/02/2026

भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा 4 सह पठितनियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोकप्रयोजना हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे)	लेक प्रयोजन का विवरण
गरियाबंद	अमलीपदर	मदांगमुडा	8.41 हे0	भेजीपदर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि, के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जनसुनवाई (दिनांक) 09/05/2026 को (समय) 11.00 बजे से (स्थान) मदांगमुड़। परनियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

(01) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण-भेजीपदर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य। (02) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -30 (03) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या - निरंक (04) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या-निरंक। (05) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या-निरंक । (06) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है-हाँ (07) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है-हाँ (08) परियोजना की लागत-2977.74 लाख। (09) परियोजना से होने वाला लाभ-कृषको को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। (10) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित, व्यय-निरंक। (11) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक-निरंक।

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी / सुझाव देना हो. तो विहित तिथि / समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

कलेक्टर गरियाबंद
एवं पदेन उप सचिव छ0ग0 शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

भू-अर्जन अधिकारी
मैनपुर

जी-262700478/2

सम्राट चौधरी ने एक तीर से किए दो शिकार

सत्येंद्र प्रताप सिंह

बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा की ओर से सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा का नामांकर दाखिल कराकर एक तीर से दो शिकार किया है। मंगल पांडे द्वारा रिक्त इस सीट पर 12 मई को मतदान होगा। दरअसल, बिहार में कुशवाहा जाति के एनडीए में दो नेता हैं। मुख्यमंत्री व भाजपा नेता सम्राट चौधरी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। एक म्यान में दो तलवार जैसी स्थिति कही जा सकती है। वैसे भी बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की राजनीति में कुशवाहा वोट के महत्व को समझाते हुए भाजपा आलाकमान पर 10 से 15 सीटों की मांग कर जबरदस्त प्रेसर बनाया था। हालांकि, भाजपा आलाकमान ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा को पांच सीटें दी थी। भाजपा आलाकमान ने जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी, तो उपेंद्र कुशवाहा ने फिर एक बार अपनी नाराजगी जाहिर की तो भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को भी छह सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी। नीतीश मंत्रिमंडल के गठन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने फिर एक बार गेम खेलकर सभी को चौंका दिया। पत्नी स्नेहलता विधायक या अपने जीते हुए विधायकों को मंत्री न बना कर बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया। इसको लेकर पार्टी के तीनों विधायक ने विद्रोह भी किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे दीपक प्रकाश को इसलिए मंत्री बनाया कि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। इसलिए मंत्रिपद बचाने के लिए एक एमएलसी का अतिरिक्त सीट मिल जाएगा। नीतीश मंत्रिमंडल भंग हो जाने के कारण दीपक फिलहाल मंत्री नहीं है। सम्राट चौधरी की सलाह पर भाजपा ने सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा को विधान परिषद के लिए नामित कर उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ा दी है। कुशवाहा अब अपने बेटे के हित को देखते हुए अपनी पार्टी का भाजपा में विलय के लिए मजबूर हो सकते हैं। भाजपा का दबाव भी है उपेंद्र कुशवाहा पर ऐसा करने के लिए। दरअसल, भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा वोट बैंक के लिए सह रही थी और इनके प्रेसर पॉलिटिक्स से भी परेशान थी। अब भाजपा को ही सम्राट चौधरी के रूप में कुशवाहा जाति का बड़ा नेता मिल गया है। सम्राट चौधरी ने एक ही तीर से दूसरा शिकार किया है पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का। जातिय राजनीति को देखते हुए भूमिहार जाति के विजय सिन्हा की भविष्य की राजनीति को भी पूरी तरह उलझा दिया है। नीतीश सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री थे। दोनों के मध्य शुरू से छत्तीस का आंकड़ा विधानसभा से लेकर सार्वजनिक स्थल पर रहा। नीतीश के बगल में बैठने व साथ चलने के लिए दृष्टिकटु दृश्य देखने को मिलता था। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के रिश्ते का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा की सुरक्षा में कटौती करते हुए उसे जेड प्लस से घटाकर जेड श्रेणी कर दिया। सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा के फैसले को भी बदल दिया। सम्राट चौधरी ने 224 राजस्व कर्मचारियों का सस्पेंशन वापस ले लिया, जिन्हें विजय सिन्हा ने राजस्व मंत्री रहते ढाई महीने पहले सस्पेंड किया था। राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को भी बदल दिया। सम्राट चौधरी को नेता चुनते वक्त विजय सिन्हा को ही नाम प्रस्ताव करना था। विजय सिन्हा ने नाम प्रस्ताव तो किये लेकिन यह भी बताना नहीं भूले की उनसे ऐसा करने को कहा गया है। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में दोनों ही उप मुख्यमंत्री जदयू के हैं। बहरहाल, भूमिहार जाति से जदयू के विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं।

क्या इस कथित स्कैम की वजह से चुनाव हार जाएंगी ममता बनर्जी? बंगाल में कैसे भाजपा ने खेला कर दिया

अभिनय आकाश

पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ 4 मई का जब नतीजे आएंगे और क्लियर हो जाएगा कि सत्ता में ममता बनर्जी की वापसी होगी या फिर इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, वह कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जमीन हिला रहे हैं। तमाम टीएमसी नेताओं की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। और कुछ नेता तो क्या कह रहे हैं टीएमसी के? टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी हर बार इस तरीके का माहौल बनाती है और उसका माहौल उल्टा ही साबित होता है। इस बार जो बंगाल में 200 पार का यह लोग बातें कर रहे हैं। इस बार वो बातें हवा-हवाई ही साबित होंगी क्योंकि 4 मई को जो नतीजे आएंगे वो टीएमसी के पक्ष में आएंगे। हालांकि बीजेपी वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी के साथ खेला होगा। इस बार बंगाल परिवर्तन चाहता है और इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। देखिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बंगाल में बिना किसी हिंसा के बिना किसी मौत के चुनाव संपन्न हुए। क्योंकि हर बार आप देखते थे चुनाव होते थे। जगह-जगह आगजनी की खबरें, हिंसा की खबरें, बूथ लूटने की खबरें सामने आती थी। कई लोगों की मौत तक की खबरें सामने आती थी। लेकिन इस बार जहां बवाल करने की कोशिश की वहां केंद्रीय बलों ने अच्छे से हिसाब किताब कर दिया और उसका नतीजा क्या हुआ? ऐतिहासिक जो मतदान प्रतिशत सामने आया वह रहा है। पिछले चुनाव में 92 से ऊपर रहा और इस बार 91 से ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा है। अब एग्जिट पोल का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि इस बार जो चुनाव के बाद बंगाल के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की आंधी में ममता बनर्जी को उड़ा रहे हैं। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स की जिसमें टीएमसी को 147 सीटें दिखाई गई हैं। जबकि बीजेपी टक्कर देती यहां नजर आ रही है। 137 सीटें बीजेपी को दिखाई गई हैं। वहीं कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस सिर्फ दो पर सिमटती नजर आ रही है। चाणक्य का सर्वे भी ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ा रहा है। इस बार चाणक्य

के सर्वे में टीएमसी को 130 से 140 सीटें दिखाई गई हैं। बीजेपी को 150 से 160 सीटें दिखाई गई हैं। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हो जाता है 4 तारीख का ये जो एग्जिट पोल है अगर यह 4 तारीख को नतीजों में बदल जाता है तो वाकई में इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा कमल खिलेगा ममता की कुर्सी हिल सकती है। राजनीतिक जानकारों की मानें तो बंगाल में इस बार अगर कोई बड़ा उलटफेर हुआ तो उसके पीछे कोयला घोटाला भी एक बड़ी वजह होगा। दरअसल, यही वो घोटाला था जिसकी पहली एफआईआर तो दर्ज हुई कुछ चुनिंदा लोगों पर। लेकिन 6 साल बाद वो जांच पहुंची एक ऐसी कंपनी के दरवाजे तक जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की चुनावी रणनीतिकार है। बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कंसलटेंसी फर्म आईपैक की जिसके कर्ताधर्ता कभी खुद प्रशांत किशोर हुआ करते थे। जिसे चलाने वाला एक शख्स फिलहाल जेल में है और बाकी दो भी खुद को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं जिन पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की मानें तो अगर इस बार बंगाल में कोई बड़ा उलटफेर हुआ तो इसकी एक वजह यह कोयला घोटाला भी होगा जिसके चलते आईपैक चारों तरफ से घिरी हुई है। ममता बनर्जी के लिए आईपैक की क्या अहमियत है? इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब आईपेक के दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ा तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आईपैक के दफ्तर पहुंच गई थी।

27 नवंबर 2020 की तारीख थी और शाम के करीब 7:00 बज रहे थे। उस वक्त देश की जांच एजेंसी सीबीआई अपने कोलकाता ऑफिस में एक एफआईआर दर्ज कर रही थी। यह एफआईआर थी पश्चिम बंगाल की कोयला कंपनी से जुड़े एक खनन घोटाले को लेकर। शुरुआत में इस एफआईआर में उस कोयला कंपनी के एंप्लाइज, कुछ सुरक्षा अधिकारियों और सीआरपीएफ से लेकर रेलवे से जुड़े लोगों को आरोपी बनाया गया था। तब यह मामला एक नॉर्मल घोटाले जैसा लग रहा था। लेकिन यह मामला गंभीर तब हुआ जब इसमें इनफोर्समेंट डायरेट की भी एंट्री हो गई और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सबको चौंका दिया। क्योंकि सीबीआई और ईडी ने यह दावा किया कि यह घोटाला कोई 10 20 करोड़ का नहीं था। यह घोटाला था पूरे 650 करोड़ रुपए का। इस घोटाले को पूरे फिल्मी तरीके से अंजाम दिया गया था और उगाही का एक ऐसा खुफिया नेटवर्क बनाया गया था जिसमें 10 से 20 रुपए के नोटों का इस्तेमाल एक कोडेड मैसेज की तरह किया जाता था और अवैध रूप से खुदाई किए गए कोयले को ऐसी कंपनियों के नाम पर भेजा जाता था जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। इस पूरे घोटाले में इकट्ठा किए गए पैसे को गुंडा टैक्स कहा गया जिसके पीछे मास्टरमाइंड था अनूप मांझी उर्फ लाला। जांच एजेंसियों ने इल्जाम लगाए कि इसी घोटाले के पैसे से इस पॉलिटिकल कंसलटेंसी फर्म को उसकी फीस अदा की गई और पैसा इसी एजेंसी के जरिए ब्लैक से व्हाइट किया गया।

प्रशांत किशोर के अलग होने के बाद से आई-पैक की पूरी कमान प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल के हाथों में है। आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र और मल्टीनेशनल कंपनी डेलॉयट में एनालिस्ट रहे प्रतीक जैन 2015 में आई-पैक के को-फाउंडर बने थे। पीके के जाने के बाद उन्होंने ही मीडिया की नजरों से दूर रहकर ममता बनर्जी की पार्टी व सरकार के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी संभाली। इस बीच, ममता सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिक्षक भर्ती, मवेशी तस्करी और कोयला घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले उजागर हुए, जिससे पूरी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई। जांच की यह आंच आई-पैक तक भी पहुंच गई है, क्योंकि एजेंसियों को गहरा शक है कि तृणमूल कांग्रेस के चुनावी अभियानों का प्रबंधन करने के लिए आई-पैक को जो भारी-भरकम रकम दी गई थी, वह वास्तव में कोयला घोटाले से कमाया गया अवैध धन ही है।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अनूप मांझी (उर्फ लाला) ने अवैध कोयला तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क चलाने के लिए लाला पैड नामक फर्जी चालान सिस्टम तैयार किया था। अवैध कोयले से भरे ट्रकों को चेक पोस्ट से सुरक्षित निकालने के लिए 10 रुपए या 20 रुपए के नोट का इस्तेमाल पासवर्ड की तरह होता था। नोट का सीरियल नंबर और ट्रक की फोटो व्हाट्सएप के जरिए भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंचाई जाती थी, जिससे ट्रक बिना जांच के पास हो जाते थे। जांच एजेंसियों (ईडी) के मुताबिक, बंगाल की कुछ कंपनियों को अवैध कोयला बेचकर करीब 650 करोड़ रुपए की नकदी जुटाई गई। इस काले धन को हवाला ऑपरेटरों के जरिए सफेद धन में बदला गया और फिर कथित तौर पर आई-पैक के माध्यम से इसका इस्तेमाल चुनावी प्रबंधन में किया गया।

इसी मामले की जांच और पैसों के लेन-देन (मनी ट्रेल) का पता लगाने के लिए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने 8 जनवरी 2026 को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित आई-पैक के दफ्तर पर छापेमारी की थी। ममता बनर्जी का सीधा दखल नहीं हुआ। ममता बनर्जी के दखल के साथ ही यह मामला कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक रंग भी लेने लगा। जिसने भाजपा और टीएमसी को आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

रहा दिति के पेट में घुस जाने की असंभवता का प्रश्न सो तो मूल में ही इन्द्र को योगमायया कहते हुवे साफ कर दिया है। जब कि योगशास्त्रानुसार एक साधारण योगी भी परकाय-प्रवेश कर सकता है, तब देवराज इन्द्र के विषय में आशङ्का का क्या काम? इसी तरह गर्भके 46 टुकड़े किये जाने पर भी जीवित रहने की आशङ्का अमोघ-वीर्य्य होने के विवेक से अपने आप समाहित हो जाती है। आगे इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक लिखा झाएगा। यहाँ इन्हीं शब्दों के साथ यह आख्यान समाप्त है।

चन्द्रमा और तारा

श्रीमद्भागवत (6।14।) में और देवी भागवत (1।11।6। 10) में लिखा है कि %चन्द्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की धर्मपत्नी तारा को हठात् छीन लिया। जब हजार बार माँगने पर भी नहीं दी तो इससे देव-दानव-युद्ध आरम्भहो गया, अन्त में श्री ब्रह्मा जी ने बीच बचाव करके किसी तरह तारा वापिस दिलवाई। इसी असें में तारा से बुध नामक एक पुत्र भी उत्पन्न हुवा था, जो चन्द्रमा का अपत्य जानकर उसे ही दिया गया। अश्लीलता की ऐनक लगाकर पुराण पढ़ने वाले महाशयों को इस आख्यान में भी अश्लीलता एवं धर्मविरुद्धता का उमढ़ा हुवा तोफान दीख पड़ा करता है, एतदर्थ इस पर भी विचार करना आवश्यक होगा।

वैदिक स्वरूप

(क) सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छद-ह्णीयमानः।

(अथर्व 5 । 17 ।2)

(ख) यामाहुस्तारकैषा विकेशीनि।

(अथर्व 5। 17 । 4)

(ग) तेन जायामन्वविन्दद् बृहस्पतिः सोमेन नीताम्।

(अथर्व 5। 175)

क्रमशः ...

विश्व टूना दिवस

शौर्य पुंज

विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। यह 2017 में पहली बार मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व में कई देश खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए टूना मछली पर निर्भर है। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में टूना मछली पालन किया जाता है, और इनकी क्षमता लगातार बढ़ रही है।

विश्व टूना दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा दिसंबर 2016 में 71/124 के प्रस्ताव को ग्रहण कर आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य संरक्षण प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट करना और यह सुनिश्चित करना

था कि टूना स्टॉक को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है। पहली बार 2 मई 2017 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्व टूना दिवस मनाया गया।

टूना की पूरे विश्व में भारी मांग है। हर देश मे इसके सर्वाधिक ग्राहक हैं, जिसके चलते बीते कुछ वर्षों में लोगों की मांग की तुलना में मछलियों की पूर्ति में अभाव दिखा है, जिसके बाद से इस मछली के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर इस मछली का शिकार किया जाता है, ताकि मानव जरूरतों की पूर्ति की जा सके, मगर अफसोस बीते कुछ वर्षों से जिस तरह से इस मछली का शिकार तेजी से बढा है, उससे इसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है।

जलवायु परिवर्तन टूना प्रजनन पर बुरा असर डाल रहा है और उन्हें समुद्र से दूर धकेलता है, जिससे लागत बढ़ती है और अक्सर गरीब तटीय समुदायों में तटीय आजीविका को खतरा होता है। समुद्री पक्षियों, शार्क, व्हेल और कछुओं को गलती से जाल में फंसने और हुक पर फंसने से रोकना भी एक सतत संघर्ष है - प्रतिष्ठित अल्बाट्रॉस की कई प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं, बड़े पैमाने पर, लेकिन केवल मछुआरों के हुक पर फंसने के कारण नहीं है।

भोजन के लिए पकड़ी जाने वाली प्रमुख टूना प्रजातियों में से दो तिहाई प्रशांत महासागर में पकड़ी जाती हैं, 23 प्रतिशत हिंद महासागर से और शेष 11 प्रतिशत अटलांटिक में पकड़ी जाती हैं। टूना की 40 से भी ज्यादा प्रजातियां शामिल हैं, लेकिन लगातार टूना के होते शिकार से अब यह विलुप्ति के कागार पर पहुंच चुकी हैं, लिहाजा इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए ही हर वर्ष 2 मई को 'वर्ल्ड टूना डे' मनाया जाता है।

टूना गर्म खून वाली शीर्ष शिकारी मछलियां होती हैं जो भोजन के लिए गहरे पानी में गोता लगा सकती हैं और शिकारियों से बचने के लिए 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती हैं। वे अत्यधिक प्रवासी होती हैं और कुछ टूना प्रजातियां हजारों मील समुद्र की यात्रा करती हैं। कुछ प्रशांत ब्लूफिन टूना 6,000 समुद्री मील से ज्यादा की यात्रा करती हैं। वे 19 मील तक की चौड़ाई वाले समूहों में भी यात्रा करती हैं।

खाड़ी देशों के लिए सांस की नली है होर्मुज

जाहिद खान

जंग के दूसरे महीने में खाड़ी देशों में रहने वाले कई प्रवासी यह लिख रहे हैं कि ईरान को अब समझौता कर लेना चाहिए। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान का इंपोर्ट-एक्सपोर्ट बंद कर दिया, तो ईरान कमजोर पड़ जाएगा और आगे चलकर उसके पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। बात सुनने में बड़ी सीधी लगती है लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। जंग में सिर्फ मिसाइल नहीं चलती, रास्ते बंद होते हैं, जहाज रुकते हैं, बाजार महंगे होते हैं, नौकरी जाती है और घर की रसोई तक आग पहुंचती है।

सबसे पहले यह समझिए कि ईरान कोई ऐसा देश नहीं है, जो पहली बार दबाव देख रहा हो। वह बरसों से पाबंदियों में जी रहा है। उसके बैंकों पर पाबंदियां लगीं, तेल पर दबाव डाला गया, जहाजों पर नजर रखी गई, कारोबार पर रोक लगी लेकिन फिर भी वह पूरा खत्म नहीं हुआ। वजह साफ है। ईरान ने मजबूरी में ही सही, लेकिन अपनी कई जरूरतें अपने अंदर पूरी करने का ढांचा बनाया है। चावल जैसी चीजों में उसे बाहर देखना पड़ता है, लेकिन खाने-पीने की बहुत सी चीजें वह खुद पैदा करता है या बनाता है इसलिए यह सोचना कि अमेरिका ने रास्ता रोका और ईरान अगले हफ्ते घुटनों पर आ जाएगा, यह बच्चों जैसी सोच है।

अब तेल की बात कीजिए। ईरान का तेल पहले ही खुले बाजार में राजा की तरह नहीं बिकता। वह दबाव में बिकता है, छूट पर बिकता है और सबसे बड़ा खरीदार चीन जैसा देश है। अमेरिका चाह कर भी चीन की जरूरतों को पूरी तरह अपने आदेश से नहीं चला सकता। चीन कोई मोहल्ले की दुकान नहीं है कि अमेरिका ने डांटा और उसने माल लेना बंद कर दिया। चीन अपना फायदा देखता है। अगर उसे सस्ता तेल मिल रहा है तो वह सौ बार रास्ता खोजेगा। यही असली बात है जिसे बहुत लोग देखना ही नहीं चाहते।

अब खाड़ी देशों को देखिए। सऊदी, कतर,

यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे देश अमीर जरूर हैं, लेकिन अमीरी और मजबूती एक ही चीज नहीं होती। बैंक में पैसा होना अलग बात है और रोज का सामान बंदरगाह तक पहुंचना अलग बात है। आपकी जेब में लाखों रुपये हों, लेकिन शहर में आटा, दाल, दूध और दवा आने का रास्ता बंद हो जाए तो पैसा भी नोटों की गड्डी बनकर पड़ा रह जाता है। होर्मुज इसी फर्क को उजागर करता है।

होर्मुज खाड़ी की सिर्फ समुद्री गली नहीं है। यह खाड़ी देशों की सांस की नली है। इसी रास्ते से तेल निकलता है, गैस जाती है, जहाज चलते हैं, बीमा कंपनियां दाम तय करती हैं और लाखों प्रवासियों की रोजी चलती है। अगर यह रास्ता बंद होता है या खतरे में आता है तो तेल का माल रुकता है, जहाज महंगे होते हैं, बीमा महंगा होता है, सामान देर से आता है और बाजार में कीमतें ऊपर जाती हैं। फिर सबसे पहले कौन पिसता है? कोई शेख नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई बड़ी कंपनी का मालिक नहीं। सबसे पहले मजदूर, ड्राइवर, छोटे कर्मचारी, होटल में काम करने वाले, दुकान पर खड़े लोग और वे प्रवासी पिसते हैं जो महीने की तनख्वाह से घर चलाते हैं।

यही वह बात है, जो खाड़ी में बैठे कई प्रवासी समझ नहीं रहे। वे ईरान को समझौते की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अपने पैरों के नीचे की जमीन नहीं देख रहे। अगर खाड़ी की कमाई रुकी तो कंपनियां पहले खर्च काटेंगी। खर्च कटेगा तो बोनस जाएगा, फिर तनख्वाह रुकेगी, फिर नौकरी जाएगी और आखिर में टिकट पकड़ाकर कहा जाएगा कि घर जाओ। संकट में हर देश पहले अपने नागरिकों को बचाता है। बाहर से काम करने आए लोगों की बारी बाद में आती है। यह बात कड़वी है, लेकिन सच है।

यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देशों की बड़ी परेशानी यह है कि खाने-पीने की बहुत सी जरूरतें बाहर से आती हैं। गेहूं, चावल, फल, सब्जी, दूध की चीजें, दालें, मांस और रोजमर्रा का सामान बड़े पैमाने पर बाहर से आता है। सऊदी और कतर कुछ हद तक खुद संभाल सकते हैं, लेकिन वे भी पूरी तरह बेफिक्र नहीं हैं। अब सोचिए, अगर होर्मुज और बाब अल मंदब दोनों रास्तों पर दबाव आ जाए तो क्या होगा? सिर्फ तेल नहीं रुकेगा, रसोई का सामान भी महंगा होगा। सिर्फ गैस नहीं रुकेगी, मजदूर की थाली भी छोटी होगी।

यही असली खेल है। ईरान पर दबाव डालने के लिए होर्मुज को आग के पास लाया जाएगा, लेकिन आग की लपटें सिर्फ ईरान की तरफ नहीं जाएंगी। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था बाहर से आने वाले सामान, बाहर जाने वाले तेल-गैस और बाहर से आए मजदूरों पर टिकी है। यह पूरा ढांचा तब तक चमकदार दिखता है जब तक रास्ते खुले हैं। रास्ते बंद होते ही असली कमजोरी सामने आती है। चमचमाती इमारतें पेट नहीं भरतीं। बंदरगाह भरते हैं। और बंदरगाह डर गए तो शहरों की चमक भी फीकी पड़ने लगती है।

इसलिए ईरान को समझौते की सलाह देना आसान है, लेकिन सवाल यह है कि समझौता किस कीमत पर? अगर समझौते का मतलब यह है कि ईरान अपनी ताकत छोड़ दे और सामने वाला अपना दबाव जारी रखे तो यह समझौता नहीं, झुकना है। हां, अगर समझौते से रास्ते खुलते हैं, पाबंदियां कम होती हैं, तेल-गैस का रास्ता सुरक्षित होता है और आम लोगों पर बोझ कम होता है तो बातचीत सबके लिए बेहतर है, लेकिन कोई भी देश सिर्फ इसलिए नहीं झुकता कि खाड़ी में बैठे कुछ लोग सोशल मीडिया पर सलाह दे रहे हैं।

अब आगे क्या हो सकता है? अगर होर्मुज का तनाव बढ़ा तो खाड़ी देशों में महंगाई बढ़ेगी। खाने-पीने का सामान महंगा होगा। जहाजों का खर्च बढ़ेगा। कंपनियां खर्च काटेंगी। छोटी नौकरियों पर खतरा आएगा। प्रवासी मजदूरों और कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ेगा। ईरान भी तकलीफ में रहेगा, लेकिन खाड़ी देश भी आराम से नहीं बैठ पाएंगे। असली चोट उन लोगों को लगेगी जिनकी तनख्वाह से घर चलता है और जिनके पीछे पूरा परिवार बैठा होता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम जंग को नक्शे पर देखते हैं, अपनी जेब में नहीं। होर्मुज नक्शे पर एक पतली सी समुद्री लाइन लगती है, लेकिन इसी लाइन पर लाखों घरों की रोटी टिकी है। जो लोग समझ रहे हैं कि ईरान झुकेगा और वे बच जाएंगे, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस जंग में अगर रास्ते बंद हुए तो सबसे पहले आम इंसान का रास्ता बंद होगा। निचोड़ यही है कि होर्मुज बंद हुआ, तो ईरान घायल होगा, लेकिन खाड़ी में रहने वाले प्रवासी की रोजी सबसे पहले खून बहाएगी।

आज का इतिहास

1866 कैलाओ की लड़ाई: पेरू के रक्षको ने स्पेनी बेड़े से लड़ाई की।
1885 बर्लिन सम्मेलन में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने स्वतंत्र स्टेट कांगो की स्थापना की।
1885 क्री और एस्सेंबोइन की एक छोटी सी ताकत ने नॉर्थ-वेस्ट रिबेलियन के दौरान मूल निवासी सबसे सफल कट कट चाकू की लड़ाई में एक बड़ी कैनेडियन बल को हराया।
1885 गुड हाउसकीपिंग पत्रिका संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार के लिए बिक्री के लिए बाजार में लायी गयी।
1918 जनरल मोटर्स के मालिक ने डेवारे के शेवरले मोटर कंपनी को ख़रीदा।
1924 नीदरलैंड ने सोवियत संघ को मान्यता देने से इनकार किया।
1933 जर्मनी में हिटलर ने ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1933 से 1945 तक हिटलर जर्मनी का शासक था।
1934 एडोल्फ हिटलर ने 2 मई, 1934 को जर्मनी में पीपुल्स कोर्ट की स्थापना की। यह जर्मन के संविधान के संचालन के बाहर स्थापित किया गया था।
1945 बर्लिन में जर्मन सैनिकों के कमांडर द्वितीय विश्व युद्ध के जनरल हेल्मथ वेइलिंग ने बर्लिन की लड़ाई को समाप्त करते हुए मार्शल जियोर्जी ज़ुकोव के नेतृत्व में सोवियत सेनाओं को शहर सौंप दिया।
1946 दो गार्ड और तीन कैदियों की हत्या के बाद कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में 2 मई, 1946 को अलकाट्राज़ की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई 2 से 4 मई 1946 तक चली।
1952 विश्व के पहले जेट विमान डी हैविलैंड कॉमेट 1 ने लंदन से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग तक अपनी पहली उड़ान भरी।
1952 पहला यात्री जेट फ्लाईट मार्ग लंदन और जोहान्सबर्ग के बीच खोला गया।
1953 हुसैन को जॉर्डन के राजा का ताज पहनाया गया।
1968 इजरायल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने टेलीविजन प्रसारण शुरू किया।
1969 ब्रिटिश महासागर के लाइनर क्वीन एलिजाबेथ 2 साउथेम्प्टन से न्यूयॉर्क शहर के लिए समुद्री यात्रा पर रवाना हुए।
1982 मौसम से सम्बंधित चैनल पहली बार केबल टेलीविजन पर प्रसारित किया गया।
1986 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की 30 वर्षीया एन. बैन्क्राफ़ उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम महिला बनीं।
1995 स्वतंत्रता-सर्ब सेना के क्रोएशियाई युद्ध ने ज़ाग्रेब की क्रोएशियाई राजधानी में रॉकेटसेट फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 7 लोग मारे गए और 175 अन्य घायल हो गए।

'आप' सांसदों के झाड़ू छोड़ कमल थामने के मायने!

अजय बोकिल

आप आदमी पार्टी (आप) के 7 राज्यसभा सांसदों का अचानक झाड़ू छोड़ कमल थामने को राजनीतिक धमाके के साथ-साथ अब पंजाब में 'ऑपरेशन लोटस' की पूर्वपीठिका के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पंजाब के पानी में कमल मुश्किल से ही खिल पाता है, लेकिन आप की झाड़ू से मोटी सींके निकाल लेने का राज्य में 10 माह बाद होने वाले विस चुनाव में आप की जमावट पर असर पड़ सकता है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि कमल के आगे झाड़ू मुरझा ही जाएगी।

कुछ राजनीतिक प्रेक्षक इसे पश्चिम बंगाल में अपनी जीत के प्रति सौ फीसदी आश्वस्ति न होने के चलते भाजपा का माइंड डायवर्शन गेम भी मान रहे हैं। बहरहाल इससे भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के खाते में कामयाबी का पहला तमगा जरूर माना जा सकता है।

दरअसल शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों द्वारा अचानक पार्टी के नेता राघव चड्ढा की अगुवाई में आप को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो जाने की खबर ने नया राजनीतिक तूफान ला दिया है। इस बड़े दलबदल के कई सियासी सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या यह बंगाल के चुनाव परिणाम अनुकूल न रहने पर नतीजों के पहले राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की नया सियासी नरेटिव गढ़ने की चाल है या फिर कभी देश में व्यवस्थागत परिवर्तन लाने के दावे के साथ सत्ता में आई चौदह साल पुरानी आम आदमी पार्टी में बिखराव का यह एक और बड़ा एपिसोड है? इस सामूहिक दलबदल अथवा पार्टी मर्जर से भाजपा को पंजाब में कुछ फायदा मिलेगा या फिर यह केवल मौका साधकर फेंकी गई राजनीतिक गुगली है, जिसका तात्कालिक लक्ष्य आप कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना है?

आप नेता कह रहे हैं कि पंजाब की जनता इन गद्दार नेताओं को सबक सिखाएगी, इसमें कितनी सच्चाई है? जाने वाले आप सांसदों का पंजाब से का क्या सम्बन्ध है और क्या इससे राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आप की वापसी की कोशिशों पर असर पड़ेगा? और यह भी कि क्या इस तगड़े झटके के बाद आम सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली में कोई अंतर आएगा या पार्टी जैसी चल रही है, वैसी ही चलती रहेगी? साथ ही इस दलबदल का दांव का देश की बाकी विपक्षी पार्टियों पर क्या असर होगा?

भारत में मुख्य रूप से चार तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं। ये हैं वैचारिक, जातिवादी, वंशवादी और व्यक्ति केन्द्रित पार्टियां। व्यक्तिवादी पार्टी किसी एक बड़े नेता

से शुरू होकर उसी पर खतम हो जाती है।

'आम आदमी पार्टी' का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ और वैकल्पिक राजनीति की कोख से हुआ था, लेकिन बाद में वह व्यक्ति केन्द्रित यानी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आधारित पार्टी में तब्दील हो गई। खुद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपो में घिर गए। पार्टी के सारे फैसले अरविंद केजरीवाल की मनमर्जी, राजी नाराजी और स्वार्थों के आधार पर होने लगे।

हालांकि आप देश की ऐसी पहली सियासी पार्टी है, जिसने अपने जन्म के मात्र दस साल में दो राज्यों में सरकार बना ली। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की निरंकुश कार्यशैली के चलते आप के जन्मदाता नेता एक-एक कर पार्टी से दूर होते गए। उसी श्रृंखला में राघव चड्ढा तथा संदीप पाठक का जाना आप के लिए बड़ा झटका है।

यह तो साफ है कि आप में असंतोष की आग भीतर ही भीतर सुलग रही थी, जिसने राघव चड्ढा को केजरीवाल द्वारा राज्यसभा के दलीय उपनेता के पद से हटाने के बाद लपट का रूप ले लिया। हैरानी की बात यह है कि पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वालों में वो अशोक मित्तल भी हैं, जिन्हें पिछले महीने ही राज्यसभा में दल का नया उपनेता बनाया गया था।

उधर आप नेता इस पूरे कांड को भाजपा का षड्यंत्र बता रहे हैं। यह साफ है कि दलबदल करने वाले सभी भाजपा के संपर्क में थे और भाजपा ने तो केवल मौके को लपक लिया। चूंकि आप के राज्यसभा में 10 में से 7 यानी कि एक तिहाई सांसद एक साथ भाजपा में गए हैं, इसलिए उन पर दलबदल का कानून लागू नहीं होगा। उनकी सदस्यता बची रहेगी। राज्यसभा में भाजपा नीत एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 148 हो जाएगी।

उधर आप नेता इस दलबदल को सीधे-सीधे पार्टी से गद्दारी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग अपनी निजी मजबूरियों के कारण बीजेपी के आगे झुक गए। पंजाब की जनता कभी गद्दारों को माफ नहीं करती है। यह बात अलग है कि खुद पंजाब में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की मौकापरस्ती और दलबदल का निरंतर इतिहास रहा है।

जो सांसद आप से भाजपा में गए हैं, उनका पंजाब से रिश्ता यह है कि वो सभी पंजाब कोटे की सीट से राज्यसभा में गए हैं। रा.स. में आप के कुल 10 सांसद हैं, इनमें से 7 पंजाब तथा 3 दिल्ली कोटे से हैं। दिल्ली वाले अभी आप में ही हैं। लेकिन इस दलबदल के बाद अब पंजाब से 'आप' का कोई राज्य सभा सदस्य नहीं रहेगा।

हालांकि इन सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। उधर 'आप' ने दलबदलू सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए कानूनी कार्रवाई के लिए करने की बात कही है, लेकिन उसका कुछ खास मतलब नहीं है। जिन सांसदों ने आप छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, उनमें से संदीप पाठक अपनी संगठनात्मक क्षमता के लिए जाने जाते हैं, राघव चड्ढा भी पार्टी के रणनीतिकारों में रहे हैं। बाकी का कोई खास जनाधार नहीं है। ऐसे में इन सब के भाजपा में आने से पार्टी को पंजाब में कोई लाभ मिलने की संभावना क्षीण ही है, सिवाय आप में घमासान का नरेटिव गढने के। वैसे भी पंजाब में भाजपा हाशिए की और हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है, बहुसंख्यक सिख उसे संदेह की नजर देखते हैं।

पिछले विस चुनाव में भी भाजपा पंजाब में 73 सीटों पर लड़ी थी और केवल 2 सीटें जीत पाई थी। उसका शिरोमणि अकाली दल के साथ चला बरसों पुराना गठबंधन भी टूट गया। जबकि पंजाब के मतदाताओं ने राज्य में पूर्व में सत्तारूढ़ कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी का विकल्प चुन लिया।

अलबत्ता इस दलबदल से पंजाब के मतदाताओं में यह संदेश तो गया ही है कि सत्तारूढ़ पार्टी आप में भीतर घमासान मचा है। हालांकि इससे नरेटिव से वहां के मतदाता का मानस कितना बदलेगा, कहना मुश्किल है।

राजनीतिक जानकार इसे पंजाब में पार्टी को मजबूत करने की भाजपा की पहल के रूप में देख रहे हैं, जो परोक्ष रूप से कांग्रेस के लिए चुनौती भी है। हालांकि कांग्रेस वहां अगला विस चुनाव किस तरह लड़ेगी, यह काफी कुछ केरल विस चुनाव नतीजे पर भी निर्भर करेगा, जहां पार्टी सत्ता की मजबूत दावेदार है, लेकिन कुशल नेतृत्व और सामंजस्य के अभाव में अगर वहां भी वह कुर्सी पर काबिज होने में नाकाम रही तो उसका असर समूची कांग्रेस और उसके मनोबल पर दिखेगा, जिसमें पंजाब भी शामिल है।

महिला आरक्षण: 2029 में 400 पार का लक्ष्य

सनत जैन

भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया। यह सत्र ऐसे समय बुलाया गया, जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। मतदान 23 एवं 29 अप्रैल को होना था। कुछ दिन पहले ही संसद का सत्र स्थगित हुआ था। यदि यह बिल इतना जरूरी था, तो ऐसी स्थिति में जब संसद चल रही थी उसी समय यह बिल लाया जा सकता था। सरकार ने विशेष सत्र क्यों बुलाया, इसको लेकर भाजपा की रणनीति को समझना जरूरी है। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है। इसमें 33 फीसदी महिलाओं को आरक्षण दिया जा चुका है। इसको लागू किस तरह से किया जाए, इसको लेकर दो महत्वपूर्ण विषयों पर सत्ता पक्ष राजनीति कर रही है। 2023 में जब महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, उस समय विपक्ष की मांग थी, इसे तुरंत लागू किया जाए। 2024 का लोकसभा चुनाव 33 फीसद महिला आरक्षण के साथ हो। उस समय सत्ता पक्ष ने विपक्ष की मांग को स्वीकार नहीं किया। सरकार ने बिल में प्रावधान किया, 2026 की जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा। उसके बाद ही महिला आरक्षण संसद और विधानसभा में लागू किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हुए। भाजपा को उम्मीद थी, महिला आरक्षण को लेकर वह 2024 के लोकसभा चुनाव को 400 से ज्यादा सीट पर चुनाव जीतेंगे। हुआ इसका उल्टा, भाजपा को मात्र 240 सीटों पर सीमित हो जाना पड़ा। भाजपा को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला। इसके बाद भाजपा ने रणनीति बदली, विपक्ष जिस तरह से सशक्त हो रहा था, उसको देखते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने विशेष सत्र बुलाकर, यह सोचा था, महिला आरक्षण बिल के नाम पर जनगणना और परिसीमन को लेकर दो नए संशोधन करेंगे। इसके माध्यम से विधानसभा तथा 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं के आरक्षण को शीर्ष पर रखा जाएगा। सरकार को भरोसा था पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सांसदों की संख्या अधिक है, चुनाव के कारण वह सत्र में भाग नहीं लेंगे। उपस्थित सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से सदन के अंदर सरकार संशोधन बिल पास करा लेगी। यदि बिल पास नहीं हो पाया, तो भी महिला आरक्षण बिल को मुद्दा बनाकर भाजपा तमिलनाडु और बंगाल के विधानसभा में बढ़त बना लेगा। वहीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं के मुद्दे पर विपक्ष को घेरेगा। संसद में दो तिहाई बहुमत से बिल पास नहीं हुआ। उसके बाद भाजपा ने इस रणनीति के तहत तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में महिला आरक्षण को मुद्दा चुनाव में बनाया। अब सभी राज्यों में प्रदर्शन और विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल के बारे में संकल्प पारित कराए जा रहे हैं।

भाजपा एक सुनियोजित रणनीति बनाकर लंबी अवधि की राजनीति करती है। भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा कमजोर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में 50 फीसदी से अधिक महिला आबादी को आरक्षण के नाम पर भाजपा राजनीति करना चाहती है। केंद्र में भाजपा की सरकार है। इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता है। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाकर और महिलाओं के पक्ष में भाजपा है, यह धारणा बनाकर भाजपा 2029 के लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें प्राप्त करने की रणनीति पर काम कर रही है। जिस तरह से भाजपा के महिला आरक्षण को लेकर आक्रामक तेवर हैं, सभी राज्यों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विधानसभा में जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर महिला आरक्षण के संकल्प पारित कराए जा रहे हैं। महिलाओं के मुद्दे को भाजपा 2029 के लोकसभा चुनाव तक विवादों में रखना चाहती है। भाजपा के रणनीतिकारों का विश्वास है, कि इस मुद्दे पर विपक्ष को दबाव में लाकर, 2026 की जनगणना में जाति जनगणना से बचा जाए। अभी केंद्र सरकार ने जाति जनगणना होगी या नहीं इसको लेकर अभी तक कोई नियम निर्धारित नहीं किए हैं। 2011 और 2026 की जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने विवाद की स्थिति बना दी है। परिसीमन सरकार अपने हिसाब से कराना चाहती है, इसमें संविधान के अभी जो प्रावधान हैं, दक्षिण के राज्यों को डराकर, केंद्र सरकार 850 लोकसभा सीटों की संख्या पर सहमत कराना चाहती है। महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा, दक्षिण के राज्यों में सेंध लगाने की रणनीति पर पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर रही है। भाजपा और संघ का शीर्ष नेतृत्व महिला आरक्षण पर दबाव बना रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष के कई राजनीतिक दल टूटकर भाजपा के साथ आ सकते है। दक्षिण के राज्यों को परिसीमन में कोई नुकसान नहीं होगा, इसके लिए भाजपा 850 सीटों का झुनझुना बजाकर दक्षिण के राज्यों के अपने पाले पर लाना चाहता है। भाजपा दक्षिण के राज्यों को भरोसा देना चाहती है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जो अनुपात अभी है, वही आगे भी बना रहेगा। परिसीमन भय दिखाकर राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए महिला आरक्षण के साथ साम-दाम-दंड-भेद की रणनीति पर परिसिमन बिल को सरकार संसद में पास कराने की योजना पर काम कर रही है। इसमें सफल होगी या नहीं, कहना मुश्किल है।

सलीम डोला को दबोच कर भारत ने तोड़ डाला दाऊद नेटवर्क

नीरज कुमार दुबे

भारत की धरती पर नशे के जहर का कारोबार कर खासतौर पर युवा पीढ़ी को बर्बादी की राह पर ले जाने को आतुर अंतरराष्ट्रीय गिरोहों पर मोदी सरकार का शिकंजा कस चुका है। वर्षों तक कानून को धता बताकर विदेशों में छिपे बैठे ड्रग माफिया अब सुरक्षित नहीं हैं। हम आपको बता दें कि एक बड़ा और निर्णायक वार करते हुए भारत ने कुख्यात तस्कर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी सलीम डोला को तुर्की से वापस लाकर अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह कार्रवाई उस पूरे नेटवर्क के खिलाफ खुली जंग का ऐलान है जिसने देश की युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचाया।

हम आपको बता दें कि कुछ महीने पहले केंद्रीय एजेंसी ने गृह मंत्रालय को एक तीन साल का खाका सौंपा था, जिसके तहत ऑपरेशन ग्लोबल हंट शुरू किया गया। इस मिशन का सीधा लक्ष्य है विदेशों में बैठे सौ बड़े ड्रग नेटवर्क को जड़ से खत्म करना। दुबई, कनाडा और यूरोप जैसे ठिकानों से चल रहे इन गिरोहों को अब भारतीय एजेंसियां वैश्विक स्तर पर घेर रही हैं। इसी मिशन का पहला बड़ा शिकार बना सलीम डोला।

मंगलवार की सुबह जब डोला को दिल्ली लाया गया, तो यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि सिस्टम की जीत थी। तुर्की की खुफिया एजेंसी और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में उसे पकड़ा गया। भारत पहुंचते ही उसे सीधे नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के कब्जे में लिया गया और आगे पूछताछ शुरू हुई। जल्द ही उसे मुंबई पुलिस को सौंपा जाएगा, जहां उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

हम आपको बता दें कि सलीम डोला कोई मामूली अपराधी नहीं है। मुंबई के भायखला इलाके में मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा यह व्यक्ति धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में उतरता चला गया। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील जैसे कुख्यात नामों से उसकी नजदीकी ने उसे अपराध की दुनिया में तेजी से ऊपर पहुंचाया। शुरुआत में गुटखा तस्करी से लेकर गांजा व्यापार तक सीमित रहने वाला यह व्यक्ति बाद में सिंथेटिक ड्रग्स का बड़ा खिलाड़ी बन गया।

उसका नेटवर्क इतना व्यापक था कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक

फैले कारखानों में एमडी और अन्य नशीले पदार्थ बनाए जाते थे। इनका वितरण देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक किया जाता था। संगली और सूरत से लेकर यूएई और तुर्की तक फैली सप्लाई चेन को वह विदेश बैठकर नियंत्रित करता था। सलीम डोला का आपराधिक इतिहास भी उतना ही चौंकाने वाला है। 1998 में पहली बार उसका नाम सामने आया, जब वह मंड्रेक्स की बड़ी खेप को हवाई अड्डे के जरिए बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था। वह पकड़ा गया, लेकिन सबूतों की कमजोर कड़ी ने उसे अदालत से बाहर निकाल दिया। इसके बाद तो जैसे यह उसका पैटर्न बन गया कि गिरफ्तारी, फिर रिहाई और फिर और बड़ा नेटवर्क।

हम आपको याद दिला दें कि 2012 में उसे अस्सी किलो गांजे के साथ पकड़ा गया, लेकिन पांच साल जेल में रहने के बाद वह बरी हो गया था। 2018 में उसे फिर पकड़ा गया था फेंटेनिल जैसी खतरनाक दवा के साथ। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में तकनीकी आधार पर मामला कमजोर पड़ा और वह जमानत पर छूट गया। यही वह मौका था जब उसने देश छोड़कर भागने की योजना बनाई और पश्चिम एशिया में जाकर अपना अड्डा जमा लिया।

विदेश में बैठकर उसने अपने काले धन को रियल एस्टेट में लगाया, जो उसके बेटे के नाम पर चल रहा था। यह साफ संकेत था कि उसका ड्रग साम्राज्य सिर्फ फैल ही नहीं रहा था, बल्कि मजबूत भी हो रहा था। उसके बेटे ताहिर और भतीजे मुस्तफा को पहले ही यूएई से वापस लाकर गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे उसके नेटवर्क को काफी झटका लगा। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। उसके जरिए उन तमाम कड़ियों तक पहुंचा जा सकेगा जो वर्षों से कानून से बचती रही हैं। यह भी सामने आ सकता है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स का यह जाल फैला हुआ है और किन किन लोगों की इसमें मिलीभगत है।

मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि नशे के कारोबार के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। एजेंसियां अब इंटरपोल नोटिस, संपत्ति जब्ती और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए इन अपराधियों को दुनिया के किसी भी कोने से खींचकर लाने को तैयार हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल गिरोहों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर जोर देते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया, मादक पदार्थ तस्करी गिरोहों को बेरहमी से कुचलने के मोदी सरकार के मिशन के तहत, हमारी स्वापक नियंत्रण एजेंसियों ने वैश्विक एजेंसियों के एक मजबूत नेटवर्क के माध्यम से सीमापार भी अपनी पकड़ मजबूत की है। उन्होंने लिखा, अब मादक पदार्थ तस्कर कहीं भी छिपें, उनके लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सलीम डोला को वापस लाया जाना, मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े मामलों के सभी भगोड़ों और संगठित अपराधिक गिरोहों के सदस्यों को न्याय के कटघरे में लाने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। मंत्रालय ने बताया कि डोला दो दशक से अधिक समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय है और वह महाराष्ट्र और गुजरात में हेरोइन, चरस, मेफेड्रोन, मैंड्रेक्स एवं मेथामफेटामीन की कई बड़ी खेपों की बरामदगी से जुड़े मामलों में शामिल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रयास तुर्किये के अधिकारियों, इंटरपोल और भारतीय एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग और समन्वित कार्रवाई का उदाहरण है।

सलीम डोला की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि अब खेल बदल चुका है। जो लोग अब तक खुद को कानून से ऊपर समझते थे, उनके लिए यह साफ संदेश है कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। यह सिर्फ शुरुआत है, और आने वाले दिनों में ऐसे कई बड़े नाम कानून के शिकंजे में होंगे। देखा जाये तो भारत अब वैश्विक स्तर पर इस जहर के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। और इस युद्ध में अब कोई नरमी नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा।

नेपाल के हित में होगी भारत से नजदीकी

डॉ सौरभ

बालेन शाह के नेतृत्व में नेपाल की नयी सरकार को सत्ता में आये हुए अभी लगभग एक महीना ही हुआ है। परंतु इसके सामने एक के बाद एक समस्या घरेलू और विदेशी मोर्चे पर लगातार आ रही है। इस सरकार को अपने पहले ही महीने में दो प्रमुख मंत्रियों के इस्तीफे के कारण अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। गृह मंत्री सुदन गुरुंग को वित्तीय लेन-देन और निवेश से संबंधित आरोपों के बीच और श्रम मंत्री दीपक कुमार साह को अपनी पत्नी को सरकारी बोर्ड में नियुक्त करने के कारण पद से हटना पड़ा है। यह स्थिति इसलिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि बालेन शाह का सत्ता में आना युवाओं के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से प्रेरित था।

ऐसे में, उनके मंत्रिमंडल में कदाचार के किसी भी आरोप से उनके सुधार एजेंडे की विश्वसनीयता स्वाभाविक ही कम हो जाती है। बढ़ती अस्थिरता के बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने विशेष कारणों का हवाला देते हुए संसद के दोनों सदनों का आज, यानी 30 अप्रैल को होने वाला सत्र स्थगित कर दिया है, जो नये नेतृत्व के कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही राजनीतिक संकट का संकेत देता है। हाल के वैश्विक तनावों, विशेष रूप से पश्चिम एशिया संकट, ने कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है, जिससे नेपाल में पेट्रोल की कीमत में भारी उछाल आया है। नेपाल उन दक्षिण एशियाई देशों में है, जहां पेट्रोल की कीमत बहुत अधिक है। इससे परिवहन, वस्तुओं और सेवाओं की लागत में वृद्धि हुई है, नतीजतन मुद्रास्फीति बढ़ी है। इस मुश्किल दौर में नेपाल ईंधन आपूर्ति के लिए लगभग पूरी तरह से भारत पर निर्भर है और पेट्रोल की उपलब्धता में व्यवधान की स्थिति कई बार अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। अपनी सरकार में भ्रष्ट लोगों की शिनाख्त करती और सड़कों पर अपनी आलोचना झेलती नयी सरकार को ईंधन की खपत कम करने के लिए दो दिन

के सप्ताहांत जैसे आपातकालीन उपाय भी लागू करने पड़े हैं। ये कदम संकट की गंभीरता और दैनिक जीवन तथा आर्थिक गतिविधियों पर इसके प्रभाव को उजागर करते हैं।

पेट्रोल और डीजल महंगा होने के कारण सीमावर्ती जिलों से काफी संख्या में लोग भारत आकर तेल ले रहे हैं। वैश्विक संकट के कारण भारत भी कच्चे तेल के संकट से अछूता नहीं है, फिर भी मुश्किल के समय पड़ोसी नेपाल और उसके लोगों की मदद की जा रही है। यह भारत की 'नेबर फर्स्ट' की नीति के अनुरूप ही है, जिसका सबूत कोरोना संकट के समय भी देखने को मिला था। हाल ही में, बालेन शाह सरकार ने 100 रुपये से ज्यादा के मूल्य पर कोई सामान विदेश से लाने पर ड्यूटी लगा दी है। भारत-नेपाल की खुली सीमा होने से हजारों लोग रोजाना अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए सीमा पर आसपास के बाजारों का उपयोग करते हैं। जनता पहले से ही महंगाई और महंगे पेट्रोल से तंग थी। अब इस नये नियम के कारण सरकार लोगों के निशाने पर है।

नेपाल के लिए, जो ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं सहित अपनी वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा भारत से आयात करता है, शुल्क संरचनाएं खुदरा कीमतों को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। भारत पर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता के कारण नेपाल में इन परिवर्तनों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, नेपाल की घरेलू उत्पादन क्षमता की कमी इस समस्या को और भी गंभीर बना देती है।

दूसरी तरफ, नेपाल सरकार अपने बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं, खासकर चीन से जुड़ी परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रही है। इनमें से कई परियोजनाएं चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ) से जुड़ी हैं, जिनमें सड़कें, जलविद्युत संयंत्र और व्यापार गलियारे शामिल हैं। बालेन शाह सरकार ने चूंकि पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है, इस कारण मौजूदा समझौतों की गहन जांच शुरू हो गयी है। खासकर ऋण स्थिरता, परियोजना की व्यवहार्यता और दीर्घकालिक आर्थिक लाभों को लेकर चिंता जतायी गयी है और कुछ परियोजनाओं की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि वे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों और वित्तीय बोझ न डालें।

बेशक चीन और भारत के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाने का प्रयास भी नेपाल कर रहा है। चीन जहां नेपाल में निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास की पेशकश करता है, वहीं भारत नेपाल का प्रमुख आर्थिक साझेदार बना हुआ है। यह नाजुक संतुलन नेपाल की विदेश नीति का केंद्रबिंदु है। नेपाल-चीन परियोजनाओं की नयी सरकार द्वारा समीक्षा विकास के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का संकेत देती है- ऐसा दृष्टिकोण, जो आर्थिक व्यवहार्यता, पारदर्शिता और भू-राजनीतिक संतुलन को प्राथमिकता देता है। विगत 10 अप्रैल को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरीशस के पोर्ट लुइस में आयोजित नौवें हिंद महासागर सम्मेलन में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत उच्च स्तरीय सहयोग जारी रखने पर जोर दिया गया था और दोनों ने सहयोग बढ़ाने और साझेदारी की गति को बनाये रखने पर चर्चा की थी। इसी कड़ी में विदेश सचिव विक्रम मिसरी के अगले महीने उच्च स्तरीय वार्ता के लिए नेपाल दौरे पर जाने की संभावना है।

बंगाल में मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार

रेनू तिवारी

15 मार्च को चुनाव आयोग द्वारा बिगुल फूंके जाने के ठीक 46 दिन बाद, पश्चिम बंगाल के हालिया इतिहास का सबसे तीखा और हाई-वोल्टेज चुनावी मुकाबला बुधवार को समाप्त हो गया। दो चरणों में हुए इस मतदान ने न केवल राजनीतिक गर्मी को चरम पर पहुँचाया, बल्कि 92.47 प्रतिशत मतदान के साथ एक नया इतिहास रच दिया है। अब सभी की निगाहें 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। इस चुनाव में बंगाल के मतदाताओं ने घर से निकलकर लोकतंत्र के उत्सव में जिस तरह भाग लिया, उसने पिछली सभी सीमाओं को लांघ दिया। यह चुनाव केवल इस बात तक सीमित नहीं रह गया है कि राज्य सचिवालय नबान्न तक कौन पहुंचेगा, बल्कि यह इस बात पर जनमत संग्रह बन गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 वर्षों के शासन के बाद भी बंगाल की केंद्रीय राजनीतिक शक्ति बनी रहती हैं या नहीं, और क्या लगातार चौथी जीत उन्हें 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत विपक्षी चेहरा स्थापित कर सकती है, या फिर भाजपा को राज्य में सत्ता का रास्ता मिल गया। दो चरणों में हुए विधानसभा चुनाव में कुल मतदान 92.47 प्रतिशत दर्ज किया गया। पहले चरण में 93.13 प्रतिशत और दूसरे में 91.66 प्रतिशत मतदान हुआ। यह स्वतंत्रता के बाद का अब तक का सर्वाधिक मतदान है। इसने 2011 के 84 प्रतिशत मतदान के रिकॉर्ड को भी पार कर लिया, जब बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थीं और 34 वर्षों के वाम मोर्चा शासन का अंत हुआ था। बनर्जी के लिए यह चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की निर्णायक लड़ाई माना जा रहा है। लगातार तीन कार्यकाल और डेढ़ दशक तक सत्ता में रहने के बाद वह न केवल सत्ता बरकरार रखने बल्कि अपने स्थापित राजनीतिक ढांचे की रक्षा के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस और बनर्जी के बीच अंतर लगभग समाप्त हो चुका है। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने आक्रामक अभियान चलाया था, तब बनर्जी ने चोटिल होने के बावजूद व्हीलचेयर पर रहकर मुकाबला किया और जीतीं, जिससे उनका कद राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विपक्षी नेता के रूप में बढ़ा। 2026 की लड़ाई अधिक कठिन मानी जा रही है। इस बार उन्हें सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप, भर्ती घोटालों और शासन संबंधी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। तृणमूल के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, यह चुनाव बंगाल की राजनीतिक पहचान की रक्षा को लेकर है। यदि दीदी फिर जीतती हैं, तो यह साबित होगा कि कल्याणकारी राजनीति और बंगाली अस्मिता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हरा सकती है। दूसरी ओर, भाजपा के लिए बंगाल अब भी अधूरा राजनीतिक लक्ष्य बना हुआ है। पार्टी का मानना है कि वह राज्य में सत्ता हासिल कर अपने अंतिम वैचारिक मोर्चे को पार कर सकती है। पार्टी का वोट शेयर 2011 में लगभग चार प्रतिशत से बढ़कर 2019 में करीब 40 प्रतिशत तक पहुंचा और 2021 में उसने 77 सीटें जीतीं, जिससे वह तृणमूल की मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन गई। एक भाजपा नेता ने कहा, हमारे लिए बंगाल अधूरा राजनीतिक मिशन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक यह एक राजनीतिक यात्रा को पूरा करने का प्रश्न है। चुनाव में सबसे बड़ा विवाद मतदाता सूचियों के एसआईआर को लेकर रहा। राज्यभर में लगभग 91 लाख नाम हटाए जाने से करीब 12 प्रतिशत मतदाता सूची से बाहर हो गए। तृणमूल ने इसे अल्पसंख्यकों, प्रवासियों, महिलाओं और गरीबों के मताधिकार को प्रभावित करने वाला कदम बताया, जबकि भाजपा ने इसे फर्जी नामों को हटाने की प्रक्रिया बताया।

दावा- डॉन 3 में गालों-गलौज और हिंसा चाहते थे रणवीर : फरहान अख्तर ने कहा-डॉन गाली नहीं देता

रणवीर सिंह और डायरेक्टर फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' को लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रणवीर इस फिल्म में हिंसा और गाली गलौज चाहते थे। फरहान के इस बात पर राजी ना होने से दोनों के बीच विवाद हुआ।

करीब 3 साल पहले शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अब अधर में लटक गया है क्योंकि रणवीर सिंह ने कथित तौर पर इस फिल्म को छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक रणवीर के फिल्म छोड़ने की वजह से फरहान अख्तर को करीब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

गाली-गलौज और हिंसा पर फंसा पेंच

एक रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह चाहते थे कि 'डॉन' का किरदार आज के दौर के हिसाब से ज्यादा हिंसक और डार्क हो। रणवीर का मानना था कि दर्शकों को पर्दे पर खून-खराबा और 'कड़ी भाषा' (गाली-गलौज) पसंद आ रही है। वे चाहते थे कि डॉन के डायलॉग्स में गालियों का इस्तेमाल हो, लेकिन फरहान अख्तर इसके सख्त खिलाफ थे।

फरहान अख्तर ने रणवीर को समझाने की कोशिश की कि 'डॉन' फ्रेंचाइजी की एक अपनी गरिमा है। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने इस किरदार को कभी भी गालियों या बेमतलब की मार-काट के जरिए पेश नहीं किया।

फरहान अपनी मूल सोच के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे। उनका तर्क था कि 'डॉन' एक स्टाइलिश और शातिर अपराधी है, न कि कोई सड़क छाप गुंडा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई और आखिरकार रणवीर ने फिल्म से हाथ पीछे खींच लिए।

रणवीर और फरहान के बीच अनबन की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई। फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के बाद रणवीर सिंह ने अचानक 'डॉन 3' से वॉकआउट कर लिया। फरहान और उनके पार्टनर रितेश सिधवानी ने इस मामले को 'प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' के सामने रखा। मीटिंग में बताया गया कि फिल्म के प्री-प्रोडक्शन पर 40 करोड़ रुपए पहले ही खर्च हो चुके थे और रणवीर ने हर स्टेज पर स्क्रिप्ट को अपनी मंजूरी दी थी।

रणवीर के फिल्म छोड़ने के बाद फरहान की कंपनी 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' ने उन पर भारी जुर्माने की मांग की है। प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि फिल्म के प्री-प्रोडक्शन और शूटिंग शेड्यूल में बदलाव की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है, इसलिए रणवीर को 40 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। हालांकि, ताजा अपडेट के मुताबिक, रणवीर सिंह फिलहाल अपनी 10 करोड़ रुपए की साइनिंग अमाउंट लौटाने पर सहमत हो गए हैं।

भारतीय साड़ी में नजर आईं पॉप सिंगर रिहाना

मुंबई ट्रिप के बाद ग्रीन-पिंक साड़ी और हैवी ज्वेलरी में दिए पोज

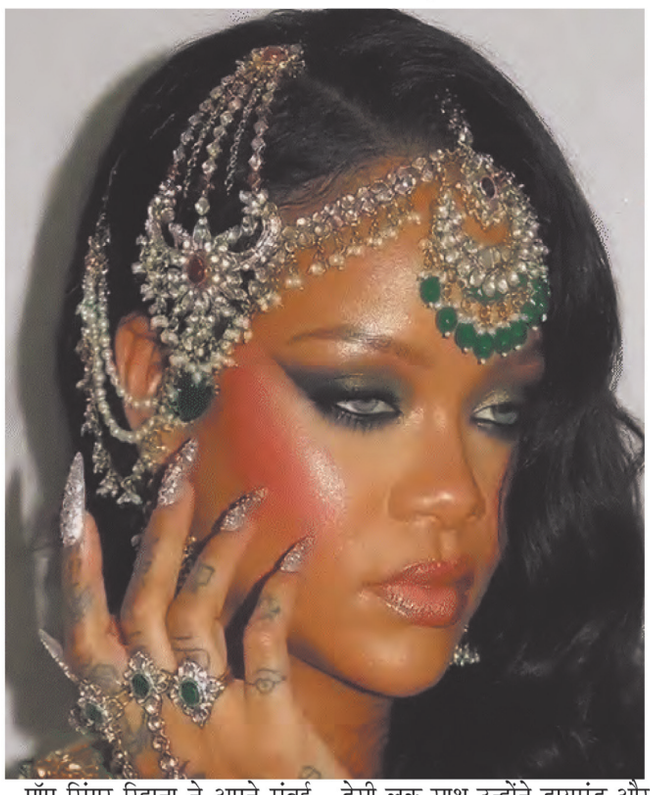

पॉप सिंगर रिहाना ने अपने मुंबई दौरे के बाद भारतीय साड़ी में फोटो शूट कराया है। रिहाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे ग्रीन और पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई हैं। इस देसी लुक साथ उन्होंने डायमंड और एमराल्ड (पन्ना) की हैवी ज्वेलरी भी पहनी है।

वीडियो में रिहाना साड़ी पहनकर खुशी से पोज देती नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी ज्वेलरी को भी वीडियो में खास तौर पर फ्लॉन्ट किया है। रिहाना के इस लुक पर फैंस सोशल मीडिया पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा पारंपरिक साड़ी और ज्वेलरी में रिहाना को देखना किसी सपने जैसा है, वे वाकई काफी सुंदर लग रही हैं।

अंबानी के घर भी पहुंची थीं रिहाना

रिहाना हाल ही में अपने ब्यूटी ब्रांड के एक प्रमोशनल इवेंट के सिलसिले में मुंबई आई थीं। यहां उन्होंने एक पॉप-अप स्टोर लॉन्च और एक प्राइवेट इवेंट में हिस्सा लिया। रिहाना प्राइवेट जेट से मुंबई पहुंचीं। इस दौरान वे रविवार को मुकेश अंबानी के घर 'एंटीलिया' भी गईं। अंबानी परिवार ने रिहाना का स्वागत बिल्कुल देसी अंदाज में किया। रिहाना ने परिवार के साथ खास लंच किया और घर के सदस्यों के साथ डांस करती भी नजर आईं।

2024 में पहली बार आई थीं भारत

यह रिहाना का भारत का दूसरा दौरा था। इससे पहले वे साल 2024 में एक बड़ी शादी (अंबानी प्री-वेडिंग) में परफॉर्म करने के लिए जामनगर आई थीं। उस वक्त उन्होंने अपने पहले भारतीय परफॉर्मेंस से काफी सुर्खियां बटोरी थीं। उस दौरान रिहाना ने वादा किया था कि वे जल्द ही दोबारा भारत आएंगी और उन्होंने अपना यह वादा पूरा भी किया।

76 साल के नाना पाटेकर ने ट्राइसेप डिप्स किए : जिम में गमछा डाले दिखे एक्टर, शिल्पा शेट्टी ने की फिटनेस की तारीफ

76 साल के एक्टर नाना पाटेकर का जिम में ट्राइसेप डिप्स करने का वीडियो सामने आया है, जिसे फोटोग्राफर-प्रोड्यूसर अतुल कासबेकर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर शेयर किया। अतुल कासबेकर द्वारा पोस्ट की गई रील में नाना पाटेकर हल्के भूरे शॉर्ट्स और सफेद बनियान में नजर आ रहे हैं। गले में गमछा डाले वे बिना किसी कठिनाई के ट्राइसेप डिप्स करते हैं और अंत में मुस्कुराते हैं। अतुल ने दावा किया कि नाना ने कुल 15 डिप्स किए।

अतुल ने पोस्ट के कैप्शन में उनकी फिटनेस की तारीफ करते हुए लिखा कि नाना ने उन्हें अपने फिटनेस गोल्स दोबारा तय करने पर मजबूर कर दिया।

शिल्पा शेट्टी-बादशाह ने तारीफ की

नाना का वीडियो सामने आने पर कई यूजर्स ने 76 साल की उम्र में इस लेवल की फिटनेस पर हैरानी जताई। वहीं, कुछ सेलेब्स ने भी प्रतिक्रिया दी। शिल्पा शेट्टी ने क्लैप इमोजी के साथ उनकी फिटनेस की तारीफ की। सिंगर बादशाह ने 'OG' लिखा। एक्टर राहुल देव और विनीत सिंह ने भी उनके फिटनेस लेवल की तारीफ की।

नाना ने हाल ही में ओटीटी डेब्यू किया

वर्क फ्रंट की बात करें तो नाना पाटेकर ने हाल ही में प्रकाश झा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज 'संकल्प' के साथ ओटीटी डेब्यू किया है। यह वेब सीरीज अमेजन एमएक्स प्लेयर पर 11 मार्च 2026 को रिलीज हुई थी। इसके अलावा नाना फिल्म 'ओ रोमियो' में भी नजर आए थे। फिल्म में उन्होंने इस्माइल खान नाम के एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था। मूवी 13 फरवरी को रिलीज हुई थी।

करोड़ों की मालकिन, एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए 290 रुपये करती हैं चार्ज?

नेहा शर्मा को बॉलीवुड में लगभग 16 साल हो चुके हैं, वह अब तक 'क्या सुपर कूल हैं हम', 'यमला पगला दीवाना 2', 'तुम बिन 2' और 'मुबारकां' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। हाल ही में नेहा शर्मा जबरदस्त ट्रोलिंग का शिकार हुईं। कुछ यूजर्स का इस बात पर ध्यान गया कि वह इंस्टाग्राम पर एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हर महीने 290 रुपये चार्ज करती हैं।

एक्सक्लूसिव कंटेंट से कमाए लाखों रुपये

जो एक्सक्लूसिव कंटेंट नेहा शर्मा शेयर करती हैं, उसे 10 हजार लोगों ने सब्सक्राइब किया है। इस तरह नेहा शर्मा ने अब तक इस कंटेंट से लगभग 29 लाख रुपये का रेवेन्यू कमाया है। लेकिन इस कंटेंट को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। यह कंटेंट सिर्फ सब्सक्राइब करने वालों को दिखता है तो पता नहीं है कि नेहा शर्मा इसमें क्या शेयर करती हैं।

सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

जब सोशल मीडिया यूजर्स को पता लगा कि नेहा शर्मा एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए 290 रुपये हर महीने चार्ज करती हैं तो उन्हें इस बात के लिए जमकर ट्रोल किया गया। एक यूजर ने लिखा, 'इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद इनके पास उसूल नहीं हैं।'

एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'हम नेहा शर्मा को इसके लिए ट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आजकल यह सामान्य बात है। लोग अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट कुछ लोगों को ही दिखाते हैं।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ट्रोलिंग के कारण नेहा शर्मा के सब्सक्राइब बढ़ गए हैं।'

डेथ एनिवर्सरी के मौके पर ऋषि कपूर की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से

ऋषि कपूर को सलमान के पिता ने धमकाया : राज कपूर ने सिगरेट पीने पर पीटा, दाऊद के साथ चाय पी, कभी अमिताभ का अवॉर्ड खरीदा

आज से 6 साल पहले सुबह खबर आई कि ऋषि कपूर अब नहीं रहे। कुछ दिन पहले तक वो गंभीर हालत होने के बावजूद हॉस्पिटल स्टाफ को हंसाते तो कभी गाना सुना रहे थे। ऋषि कपूर की इकलौती बेटी रिद्धिमा कहती हैं, 'सब अचानक हुआ, वो बहुत डरावना दिन था। अचानक एक खालीपन आ गया। एक सूनापन, उनकी जिंदगी उनकी मौजूदगी लार्जर देन लाइफ थी।'

ऋषि कपूर 3 साल के थे, जब वो पिता राज कपूर की फिल्म 'श्री 420' में चॉकलेट की लालच में नजर आए। तब से उनका सिनेमा से ऐसा रिश्ता जुड़ा, जो ताउम्र कायम रहा। 1973 की फिल्म 'बॉबी' से फिल्मों में आए ऋषि कपूर उर्फ चिंटू ने 'रफूचक्कर', 'कर्ज', 'प्रेम रोग', 'चांदनी' जैसी बेहतरीन फिल्में कीं। बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने 'अग्निपथ', 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर', 'कपूर एंड संस', 'नमस्ते लंदन', 102 नॉट आउट जैसी फिल्में कीं। रिद्धिमा कहती हैं, 'उनमें सिनेमा के लिए जुनून था। बहुत पैशनेट थे। हम उनकी फिल्मों के सेट पर जाते थे। वो एक कोने में किरदार की तैयारी करते थे।'

बेटी रिद्धिमा के मुताबिक, पिता ऋषि कपूर लार्जर देन लाइफ जिंदगी जीते थे। इसका परिणाम वो किस्से हैं, जो उनकी बेबाकी, हाजिरजवाबी, गुस्से और मजेदार व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। कभी उन्होंने अमिताभ को दिया जा रहा अवॉर्ड खरीदकर अपने नाम किया, तो कभी सलमान खान के पिता की धमकी का जवाब दिया। डिंपल कपाड़िया से अफेयर भी चर्चा में रहा और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई उनकी मुलाकात भी विवाद की वजह बनी।

किस्सा-1, चॉकलेट की लालच में 3 साल के ऋषि कपूर ने की एक्टिंग

4 सितंबर 1952

बॉम्बे के मटुंगा स्थित राज कपूर बंगलो में कृष्णा कपूर ने बेटे ऋषि को जन्म दिया। वो तीन भाइयों में मंझले थे। रणधीर कपूर (करीना-करिश्मा के पिता) बड़े थे और राजीव कपूर (छोटे)। पिता राज कपूर शोमैन थे। ऋषि महज 3 साल के थे, जब पिता राज कपूर, नरगिस के साथ श्री 420 बना रहे थे।

फिल्म के मशहूर गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में जब राज कपूर को चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत पड़ी, तो वो अपने बच्चों को सेट पर ले आए। गहरी आंखें और चबी गाल वाले ऋषि हर किसी का ध्यान खींच लिया करते थे। सेट पर उन्हें दूसरे बच्चों के साथ बारिश में भीगना था, लेकिन नाजुक चिंटू जी के ऊपर जैसे ही बूंदें गिरतीं, वो रोना शुरू कर देते।

कई बार शॉट खराब हुए और रील्स बर्बाद होने लगीं। तब नरगिस धीरे से उनके पास आईं और कहा, अगर वो बिना रोए शॉट पूरा करते हैं, तो वो उन्हें ढेर सारी चॉकलेट देंगी। खाने-पीने के शौकीन चिंटू राजी क्यों न होते। और इस तरह ऋषि कपूर ने 1955 की फिल्म श्री 420 से बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्मों में एंट्री ली।

किस्सा-2, कार में भरकर मुगल-ए-आजम के सेट पर ले जाते थे दादा पृथ्वीराज कपूर

1960 में आई फिल्म मुगल-ए-आजम में ऋषि कपूर के दादाजी पृथ्वीराज कपूर ने बादशाह अकबर का किरदार निभाया था। वो अक्सर घर के सभी बच्चों को कार में भरकर सेट पर ले जाते थे। तब ऋषि कपूर 6 साल के थे। सारे बच्चे मधुबाला की खूबसूरती देख रहे थे, लेकिन ऋषि कपूर की नजरें दिलीप कुमार पर टिकी थीं।

ऋषि कपूर को मिले अवॉर्ड

- 1970 नेशनल फिल्म अवॉर्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट (मेरा नाम जोकर)
- 1974 फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड (बॉबी)
- 2008 फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
- 2009 रूसी सरकार से विशेष सम्मान
- 2011 फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर क्रिटिक अवॉर्ड (दो दूनी चार)
- 2016 स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
- 2017 फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवॉर्ड (कपूर एंड संस)

किस्सा- 3, राज कपूर ने सिगरेट पीते देख कर दी पिटाई

करीब 15 साल की उम्र में दोस्तों की वजह से ऋषि कपूर को सिगरेट पीने की लत लग गई। वो मुंबई के चैंपियन स्कूल के बाहर कोकाकोला स्टैंड की दुकान से अहमद नाम के दुकानदार से सिगरेट लिया करते थे। एक समय में दुकान में उनकी 300 रुपए उधारी हो गई। एक दिन गुस्से में अहमद से कहा कि अगर उधारी नहीं चुकाई, तो वो राज कपूर को बता देंगे। एक दिन ऋषि कपूर पिता के मेकअप मैन के साथ सिगरेट के कश लगा रहे थे, तभी राज कपूर पहुंच गए। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद राज कपूर ने ऋषि कपूर को खूब पीटा। स्टार बनने के बाद ऋषि कपूर 300 रुपए उधार चुकाने गए थे, लेकिन तब अहमद ने पैसे नहीं लिए और उन्हें बस गले लगा लिया।

किस्सा-4, डिंपल कपाड़िया को दी, गर्लफ्रेंड की दी हुई अंगूठी

ऋषि कपूर को स्कूल के दिनों में पारसी यास्मीन नाम की लड़की से पहला प्यार हुआ। उन्होंने ही बॉबी से डेब्यू करने वाले ऋषि कपूर को वजन घटाने में मदद की थी। एक दिन यास्मीन ने ऋषि को एक

पुण्यतिथि पर विशेष

अंगूठी गिफ्ट की, जो वो हमेशा पहने रखते थे। बॉबी की शूटिंग के समय ऋषि कपूर और डिंपल में गहरी दोस्ती हो गई। डिंपल अक्सर उनकी अंगूठी पहन लिया करती थीं। धीरे-धीरे वो अंगूठी डिंपल की ही हो गई।

डिंपल को शादी के लिए प्रपोज करते हुए राजेश खन्ना ने ऋषि कपूर की वो अंगूठी उतरवाकर समुद्र में फेंकी और फिर अपनी अंगूठी पहनाई थी। तब रिपोर्ट्स आईं कि ऋषि ने ही वो अंगूठी डिंपल को पहनाई थी। यही वजह रही कि ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड यास्मीन ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। डिंपल कपाड़िया और ऋषि की डेब्यू फिल्म बॉबी (1973) सुपरहिट रही थी। लेकिन फिर डिंपल ने राजेश खन्ना से शादी कर फिल्मों से ब्रेक ले लिया।

किस्सा-5, पैसे देकर खरीदा पहला अवॉर्ड, अमिताभ से हुई अनबन

फिल्म बॉबी (1973) के लिए ऋषि कपूर को फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला था। उस साल ऋषि के अलावा अमिताभ बच्चन भी फिल्म जंजीर के लिए नॉमिनेटेड थे। हर तरफ चर्चा थी कि अवॉर्ड अमिताभ को ही मिलेगा, लेकिन ऋषि कपूर ने 30 हजार रुपए में वो अवॉर्ड खरीद लिया। ऐसा उन्होंने पीआरओ तारकनाथ गांधी और अपने सेक्रेटरी घनश्याम के कहने पर लिया। जैसे ही अमिताभ बच्चन को पता चला कि ऋषि ने अवॉर्ड खरीदा है तो दोनों के बीच कोल्डवॉर छिड़ गया। ऋषि ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम-खुल्ला में लिखा कि उन्हें अवॉर्ड खरीदने का पछतावा था और शर्म थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन उनसे नाराज हो गए थे।

किस्सा- 6, फ्यूचर वाइफ नीतू सिंह से लगवाते थे एक्स गर्लफ्रेंड यास्मीन को कॉल, होटल में देख दिल टूटा

ऋषि कपूर यास्मीन से रिश्ता बरकरार रखना चाहते थे। फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग के समय ऋषि, को-स्टार और दोस्त नीतू सिंह से यास्मीन को कॉल लगवाते थे, लेकिन जवाब नहीं मिलता था। एक दिन ऋषि ताज होटल में थे, तभी उन्हें यास्मीन दिखीं, जो वहां, ऋषि के ही एक पुराने दोस्त के साथ आई थीं। ये देख ऋषि कपूर का दिल टूट गया। 2 हजार लेकर पहुंचे ऋषि कपूर ने 18 हजार रुपए की शराब पी ली। बाद में उनका मैनेजर से खूब झगड़ा हुआ।

किस्सा-7, सलीम-जावेद ने दी थी करियर तबाह करने की धमकी, जवाब में कहा- करके दिखाओ

जंजीर, शोले लिखने वाले सलीम-जावेद का 80 के दशक में बड़ा नाम था। हर कोई उनकी लिखी फिल्म करना चाहता था। एक बार राइटर जोड़ी ने ऋषि कपूर को फिल्म ऑफर की, जो उन्होंने ठुकरा दी। सलीम-जावेद इससे चिढ़ गए। एक दिन उनकी मुलाकात प्लेमेट क्लब में हुई। सलीम खान (सलमान के पिता) ने ऋषि को देखते ही कहा- तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फिल्म ठुकराने की। जवाब मिला- मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। सलीम ने गुस्से में कहा- तुम जानते नहीं हो क्या कि इंडस्ट्री में आजतक हमें किसी ने इनकार नहीं किया। हम तुम्हारा करियर तबाह कर सकते हैं।

ये सुनकर ऋषि कपूर ने कहा- आप मुझे बर्बाद करने के लिए क्या कर सकते हैं। सलीम ने कहा- तुम्हारे साथ कौन काम करेगा, क्या तुम जानते हो, हमने राजेश खन्ना को जंजीर ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से इनकार किया था। हमने उनके साथ कुछ नहीं किया, बस उनकी जगह अमिताभ को ले आए, जिन्होंने उन्हें बर्बाद कर दिया। हम तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। इस पर ऋषि कपूर ने कहा- गो अहेड (आगे बढ़ो) और मुझे बर्बाद करके दिखाओ।

किस्सा-8: दाऊद इब्राहिम ने कॉल कर चाय पर किया इनवाइट

साल 1988 में ऋषि कपूर दोस्त बिट्टू आनंद के साथ आशा भोसले का प्रोग्राम अटेंड करने दुबई गए थे। एयरपोर्ट पर अचानक एक शख्स उनके पास आया और उन्हें मोबाइल थमाते हुए कहा, दाऊद साहब बात करेंगे। दाऊद ने कॉल पर कहा- किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना। ये सुनकर ऋषि कपूर डर गए। कुछ समय बाद दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड ने उनसे कहा कि दाऊद आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। ऋषि कपूर इनकार नहीं कर सके। उसी शाम उनके होटल में एक रोल्स रॉयस आई, जो उन्हें एक अनजान जगह ले गया। दाऊद ने ऋषि से मुलाकात की और कहा- मैं ड्रिंक नहीं करता, इसलिए आपको चाय पर बुलाया। ये मुलाकात 4 घंटे चली।

किस्सा- 9, नीतू के लिए गिफ्ट की जगह ले आए कुत्ते के बिस्कुट

ऋषि कपूर ने 13 फिल्मों में को-स्टार रहीं नीतू सिंह से 1980 में शादी की थी। इस शादी से कपल को दो बच्चे बेटा रणबीर और बेटी रिद्धिमा हुईं। एक बार ऋषि कपूर अमेरिका गए, तो नीतू सिंह ने फरमाइश कर कई चीजों की लिस्ट थमा दी। कुछ दिनों बाद ऋषि कपूर 3 सूटकेस के साथ लौटे। नीतू को लगा कि सूटकेस में उनकी चीजें होंगी, लेकिन असल में उनमें पालतू कुत्ते के बिस्कुट थे। इस बात से ऋषि-नीतू का खूब झगड़ा हुआ था।

किस्सा-10, मूड खराब हुआ तो डायरेक्टर को हाईवे पर कार से उतारा

ऋषि कपूर हमेशा से ही गुस्सैल थे। फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने से पहले ही कह देते थे पहले मेरी शर्तें सुनो, मंजूर हो, तब ही बात आगे होगी। शर्त होती थीं, सुबह 10 से पहले रात 8 के बाद शूट नहीं करूंगा। नाइट सीन हो, तब भी दिन में सेट बनाकर करो। संडे शूट नहीं करूंगा। एक दिन फिल्म सिटी में शूटिंग करते हुए एक डायरेक्टर ने कहा कि वो उन्हें स्क्रिप्ट नरेशन देना चाहते हैं। वो बिजी थे, तो डायरेक्टर ने कि पैकअप के बाद जब आप घर निकलो, तो मैं रास्ते में मेकअप वैन में ही सुना दूंगा।

ऋषि मान गए। मेकअप वैन में ऋषि कपूर हमेशा पीछे की तरफ कमरे में न बैठकर ड्राइवर के साथ आगे बैठते थे, क्योंकि उन्हें हिलते हुए रूम पसंद नहीं आते थे। लेकिन उस दिन ड्राइवर की वजह से उन्हें पीछे रूम में बैठना पड़ा। वो पहले ही चिढ़े हुए थे, तभी डायरेक्टर ने लगातार बोलना शुरू कर दिया। फिल्म में क्या अच्छा, कैसी होगी, हीरो क्या करेगा, वगैरह-वगैरह।

मेकअप वैन हाईवे पर थी। फिल्म की ज्यादातर कहानी एक रात की थी तो ऋषि कपूर का और इंट्रेस्ट कम हो गया, क्योंकि वो रात को शूट नहीं करते थे। तभी उन्होंने पूछा, सेट कहां होगा, तो डायरेक्टर ने काफी एक्साइटमेंट में कहा, ज्यादातर शूटिंग रोड पर होगी। ये सुनते ही ऋषि कपूर और चिढ़ गए। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को आवाज दी और कहा- गाड़ी रोको, और उस डायरेक्टर को हाईवे पर ही उतार दिया और वहां से निकल गए।

50 साल का करियर और 121 फिल्में-

अपने 50 सालों के फिल्मी करियर में ऋषि ने तकरीबन 121 फिल्मों में काम किया। 1973 से 2000 के बीच ऋषि ने 92 रोमांटिक फिल्मों में काम किया जिनमें से 36 फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। इनमें 'कर्ज', 'दीवाना', 'चांदनी', 'सागर', 'अमर अकबर एंथनी', 'हम किसी से कम नहीं', 'प्रेम रोग', 'हिना' जैसी फिल्में शामिल हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

टीएमसी पहले से ही बना रही है हार के बहाने : भाजपा

नईदिल्ली। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावालाने का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल आने के बाद साफ दिख रहा है कि पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार बना सकती है। टीएमसी को बड़ी हार मिल सकती है। इसी वजह से टीएमसी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और तरह-तरह के आरोप लगा रही है। पूनावाला ने कहा कि टीएमसी पहले से ही हार के बहाने बना रही है। वह घबराहट में ऐसा कर रही है। बीजेपी नेता राम कृपाल यादव ने भी टीएमसी के ईवीएम छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को नकार दिया है और कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए कहा कि उसने पूरी ईमानदारी से काम किया है, नतीजे आने पर सब साफ हो जाएगा। दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर मतगणना केंद्र में ममता बनर्जी करीब चार घंटे रहीं और रात 12 बजे के बाद बाहर निकलीं।

बंगाल चुनाव हार रहीं ममता बनर्जी : उपेंद्र कुशवाहा

पटना। बिहार के पटना में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें पता है कि उनकी हार निश्चित है, इसलिए वे घबराई हुई हैं, वे ऐसी स्थिति पैदा कर रही हैं ताकि हारने के बाद वे कह सकें कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई थी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी को इसका अंदाजा हो गया है कि पश्चिम बंगाल से उनकी विदाई हो गई है। मतदाताओं ने दोनों ही चरणों में टीएमसी को करारी शिकस्त दी है। सुनियोजित तरीके से निर्वाचन तंत्र की विश्वसनीयता को तार-तार करने के लिए ऐसे आरोपों को लगाने का सिलसिला टीएमसी के लोगों की तरफ से जारी है, इन्हें जहां लगता है कि ये लोग चुनाव हारने वाले हैं, वहां ये लोग इसी तरह से आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग ने इनके एक-एक आरोप का जवाब दे दिया है।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अग्रिम जमानत

नईदिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी कानूनी जीत मिली है। शीर्ष अदालत ने असम पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि और जालसाजी के मामले में खेड़ा को गिरफ्तारी से पहले जमानत (अग्रिम जमानत) दे दी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से संबंधित है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चांदुरकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई तब की, जब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने खेड़ा को यह भी निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करें और जब भी ज़रूरत हो, पुलिस के सामने पेश हों। उनसे यह भी कहा गया है कि वे जांच या ट्रायल के दौरान सबूतों को प्रभावित करने या उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें, और सक्षम कोर्ट की पहले से अनुमति लिए बिना देश छोड़कर न जाएं।

तमिलनाडु में 4 मई को आएगी अच्छी खबर : एमके स्टालिन

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए प्रयासों का फल 4 मई को मिलेगा। 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। स्टालिन ने यहां एक मई दिवस कार्यक्रम में कहा '4 मई मतगणना दिन को हम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई कड़ी मेहनत का फल पाने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं है और न ही जरा सा भी विचलन है।' उन्होंने आगे कहा, 'किसी को भी यह मान लेने की जरूरत नहीं है कि मैं केवल एग्जिट पोल के आधार पर बोल रहा हूं।' डीएमके प्रमुख स्टालिन ने कहा कि चुनाव परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आएगी। यह कहते हुए कि डीएमके का शासन दर्शन और सिद्धांतों पर आधारित है। स्टालिन ने कहा, यह जारी रहेगा। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरई की महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया।

पीएमके नेता ने तमिलनाडु में एनडीए की जीत का दावा किया

चेन्नई। पीएमके नेता डॉ. अंबुमणि रामदास ने शुक्रवार को कहा वोटों की गिनती के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से सतर्क और समन्वित रहने का आग्रह किया। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। वहीं, चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक बयान में कहा, 'चुनाव प्रचार और मतदान इन दो चरणों में से तीसरा चरण मतगणना का है। यानी निस्संदेह यह दिन सबसे महत्वपूर्ण है।' अंबुमणि ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान एआईएडीएमके, भाजपा और एएमएमके सहित गठबंधन दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय अच्छा था। उन्होंने कहा, 'चुनाव प्रचार के दौरान ही हमें स्पष्ट रूप से यह पता चल गया था कि इस चुनाव में जीत हमारी ही होगी।' उन्होंने आगे कहा, 'इसके अलावा, मतदान के दिन हमने लोगों को सत्ताधारी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए देखा।'

आत्मनिर्भर लद्दाख की ओर बढ़ते कदम!

अमित शाह ने करगिल में डेयरी संयंत्र की रखी आधारशिला

कारगिल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में श्वेत क्रांति को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को करगिल में 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एक आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई यह परियोजना लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी।

अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये पहल पेश की गई हैं। इनमें मोबाइल दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं, आधुनिक दूध शीतलन प्रणाली और डेयरी अवसंरचना को मजबूत करना शामिल है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है।

यह परियोजना मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के तहत लागू की जा रही है, जिसमें 12.74 करोड़ रुपये का अनुदान, 10 करोड़ रुपये की सहायता राष्ट्रीय डेयरी विकास फाउंडेशन से और शेष राशि एलयूटीडीसीएफ फंड के माध्यम से (हिमाचल प्रदेश प्रशासन के जरिये) उपलब्ध कराई जा रही है। यह संयंत्र 350 किलोवाट सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली पर चलेगा जिससे ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में स्वच्छ तथा टिकाऊ संचालन सुनिश्चित होगा।

दूध संग्रह के लिए आधुनिक मोबाइल 'मिल्क कलेक्शन' एवं 'कूलिंग सिस्टम' स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों से सीधे दूध संग्रह, गुणवत्ता संरक्षण और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि ये कदम लद्दाख के डेयरी क्षेत्र के आधुनिकीकरण, किसानों की आय बढ़ाने और खरीद प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। साथ ही बिजली से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने, दूध संग्रह को सुव्यवस्थित करने और किसानों को समय पर डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने के उपाय भी किए गए हैं। भारतीय सेना के साथ नियमित दूध आपूर्ति व्यवस्था से इस क्षेत्र में डेयरी गतिविधियों को स्थिर बाजार मिला है जिससे संचालन की विश्वसनीयता बढ़ी है।

डिजिटल सुधारों के तहत एआई आधारित निगरानी प्रणाली, मोबाइल दूध संग्रह इकाइयां और जलवायु अनुकूल शीतलन समाधान लागू किए गए हैं ताकि गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे। इन पहलों का असर अब दिखने लगा है। एक गांव के 74 किसानों से शुरू होकर अब यह नेटवर्क करीब 1,700 किसानों तक पहुंच गया है। दैनिक दूध संग्रह लगभग 7,000 लीटर तक पहुंच गया है और किसानों को कुल भुगतान 15 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। यह सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र हजारों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ देगा, उनकी आय बढ़ाएगा और स्थानीय कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेगा।

अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल प्रयोगशालाओं की तैनाती, कोल्ड चेन नेटवर्क का विस्तार और डिजिटल ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन सिस्टम (एएमसीएस) को अपनाने जैसे कदम भी जारी हैं जिससे दक्षता बढ़ेगी। इसके अलावा पनीर और दही जैसे उत्पादों के जरिये मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मदर डेयरी, सफल और धारा जैसे ब्रांडों के साथ साझेदारी कर उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने की योजना है। यह कार्यक्रम सहकारी ढांचे के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित करने के साथ-साथ ग्रामीण विकास, आय स्थिरता एवं जीवन स्तर सुधार की दिशा में एक व्यापक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है जो 'आत्मनिर्भर लद्दाख' और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अमित शाह के लद्दाख दौरे पर बिफरी कांग्रेस

धार्मिक आयोजनों की आड़ में मुद्दों से ध्यान भटका रही केंद्र सरकार

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लद्दाख दौरे को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक आयोजनों के जरिए ध्यान भटका रही है, जबकि लद्दाख के लोगों की बुनियादी मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है।

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि गृह मंत्री इस समय पिपरहवा से जुड़े पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के गौरव में डूबे हुए हैं, लेकिन लद्दाख के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों, राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के तहत संरक्षण, और भूमि व रोजगार की सुरक्षा पर पूरी तरह खामोश हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दे सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि लद्दाख की पहचान, संस्कृति और संसाधनों की सुरक्षा से जुड़े हैं, जिन पर केंद्र सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।

रमेश ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 1949 के लद्दाख दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी बौद्ध पवित्र अवशेषों को लेकर महत्वपूर्ण पहल की गई थी। उन्होंने बताया कि 1851 में ब्रिटिश शासन के दौरान सांची स्तूप से भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महा मोग्गलान के अवशेष निकालकर लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखे गए थे।

आजादी के बाद 14 जनवरी 1949 को इन अवशेषों को भारत वापस लाया गया। नेहरू ने इन्हें कोलकाता स्थित महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को सौंपा। इसके बाद जुलाई 1949 में नेहरू ने चार दिनों का लद्दाख दौरा किया।

इस दौरे के दौरान प्रमुख बौद्ध धर्मगुरु कुशोक बकुला रिनपोछे ने उनसे अनुरोध किया कि इन पवित्र अवशेषों को लद्दाख भी लाया जाए ताकि वहां के लोग भी दर्शन कर सकें। यह मांग बाद में पूरी हुई और मई 1950 में इन अवशेषों को 79 दिनों तक लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया। रमेश ने कहा कि इसके बाद इन अवशेषों को यांगून (म्यांमार), कोलंबो (श्रीलंका) और सांची में स्थापित किया गया।

कांग्रेस ने एक दिन पहले भी केंद्र सरकार से पूछा था कि वह लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत लाने के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। पार्टी का कहना है कि लद्दाख के लोग लंबे समय से इन मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है।

गौरतलब है कि अमित शाह गुरुवार को लद्दाख पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारत में पहली बार आयोजित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में हिस्सा लिया।

पंजाब विधानसभा में भारी हंगामा!

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा का मज़दूर दिवस को समर्पित विशेष सत्र शुक्रवार को भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि वह सदन की कार्यवाही में शराब के नशे में शामिल हुए थे।

इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री के मेडिकल टेस्ट की मांग की है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस मुद्दे को और तेज़ करते हुए मांग की कि सभी विधायकों का अल्कोहल मीटर टेस्ट कराया जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य के मुखिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए सच का पता लगाने के लिए हर विधायक का टेस्ट होना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल ने भी मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला, असेंबली के वीडियो जारी किए और गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने इसे बहुत शर्मनाक बताया कि भगवंत मान कथित तौर पर मज़दूर दिवस पर शराब पीकर असेंबली में आए थे। उसने जनता से सदन में मुख्यमंत्री के व्यवहार पर गौर करने को कहा और उनके आचरण की कड़ी निंदा की। अकाली दल ने आगे मांग की कि सच सामने लाने के लिए भगवंत मान पंजाब की जनता के सामने डोप टेस्ट कराएं।

राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक बड़े कानूनी मामले में बड़ी राहत दी है। जस्टिस विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले विवादित बयान को लेकर दाखिल याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस मामले में न तो मुकदमा दर्ज होगा और न ही कोई कानूनी कार्यवाही चलेगी। यह मामला पिछले वर्ष कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' के उद्घाटन के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के उस बयान को देशद्रोह की श्रेणी में मानते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमारी लड़ाई भाजपा, आरएसएस और खुद 'इंडियन स्टेट' से है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 8 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को ओपन कोर्ट में फैसला सुनाते हुए जस्टिस विक्रम डी चौहान ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की मांग में कानूनी आधार का अभाव है। अदालत के इस रुख से यह साफ हो गया है कि राजनीतिक बयानों में व्यवस्था के विरोध को सीधे तौर पर आपराधिक कृत्य या देशद्रोह के चश्मे से नहीं देखा जा सकता।

खेल
प्रमुख समाचार

एशियाई चैंपियनशिप से बाहर रहेंगी चानू

नई दिल्ली। भारत की ओलंपिक पदक विजेता और स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू अगले महीने गांधीनगर में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप में भाग नहीं लेंगी। कंधे की चोट के चलते उन्होंने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। चानू का मुख्य लक्ष्य इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करना है, जिसके लिए वह कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहतीं। उनका यह रणनीतिक निर्णय सुनिश्चित करेगा कि वह महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह से फिट और तैयार रहें।

भारोत्तोलन एक ऐसा खेल है जिसमें शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, और चानू जैसी शीर्ष स्तर की एथलीट के लिए चोट से बचाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाली मीराबाई का मानना है कि उनकी शारीरिक स्थिति सर्वोच्च प्राथमिकता है। एशियाई चैंपियनशिप से बाहर रहकर, उन्हें अपनी चोट से पूरी तरह उबरने और आगामी मेगा-इवेंट्स के लिए अपनी शक्ति और तकनीक को निखारने का पर्याप्त समय मिलेगा। यह कदम उनके दीर्घकालिक करियर के लिए भी बुद्धिमानी भरा है, ताकि वह भविष्य में भी भारत के लिए पदक जीतती रहें। मीराबाई चानू का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल होंगे। इन खेलों में वह अपने पसंदीदा 48 किग्रा वर्ग में उतरेंगी, जहां उन्हें स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में उनका प्रदर्शन हमेशा ही बेहतरीन रहा है और वह एक बार फिर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल करने की उम्मीद कर रही हैं। हाल ही में मोदीनगर में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्होंने कुल 205 किग्रा (89 किग्रा स्नैच और 116 किग्रा क्लीन एंड जर्क) भार उठाकर 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बन सकता है

नईदिल्ली। चीफ इकनॉमिक एडवाइजर वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि अगर भारत लगातार तेज आर्थिक वृद्धि बनाए रखे और तकनीक व रिसर्च में मजबूत प्रगति करे, तो वह 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने आईआईटी मद्रास में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत को डॉलर टर्म में लगभग 12त्न की सालाना वृद्धि की जरूरत होगी। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था करीब 3.91 ट्रिलियन डॉलर की है और अनुमान है कि अगले छह वर्षों में यह 7.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। नागेश्वरन ने यह भी कहा कि भारत को लंबे समय तक उच्च विकास बनाए रखने के लिए अपनी संरचनात्मक (ढांचागत) समस्याओं को दूर करना होगा, खासकर बदलते भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 993 रुपये बढ़े

नईदिल्ली। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच 1 मई 2026 से कमर्शियल सिलेंडर महँगा हो गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बताया कि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत शुक्रवार से 993 रुपये बढ़ा दी गई है, जिससे दिल्ली में इसका नया रेट 3,071.5 रुपये हो गया है। हालांकि, इस बड़ी तेल कंपनी ने कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी ने यह भी कहा कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद पेट्रोल और डीज़ल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि वैश्विक ऊर्जा लागत अभी भी ऊँची बनी हुई है। घरेलू एयरलाइनों के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे विमानन क्षेत्र को कुछ राहत मिली है।

विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपए निकाले

नईदिल्ली। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगातार बिकवाली जारी रखी और अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपए (6.5 अरब डॉलर) की निकासी की। इसकी मुख्य वजह बढ़ते भूराजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता रही, जिससे निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई। हालिया आउटफ्लो के साथ ही 2026 के पहले चार महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का कुल आउटफ्लो 1.92 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पूरे 2025 के 1.66 लाख करोड़ रुपए के आउटफ्लो से काफी ज्यादा है। यह आंकड़े एनएसडीएल के डेटा से सामने आए हैं। 2026 में फरवरी को छोड़कर सभी महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक नेट सेलर रहे। जनवरी में 35,962 करोड़ रुपए की निकासी हुई, जबकि फरवरी में 22,615 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो पिछले 17 महीनों में सबसे अधिक मासिक निवेश था।

जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में 2.43 लाख करोड़ रू. के पार

नईदिल्ली। अप्रैल में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) कलेक्शन 8.7 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड लगभग 2.43 लाख करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले सबसे अधिक कलेक्शन अप्रैल पिछले वर्ष में 2.23 लाख करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया गया था। सरकार ने शुक्रवार को जीएसटी के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के अनुसार, घरेलू लेनदेन से ग्रॉस रेवेन्यू 4.3 प्रतिशत बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जबकि आयात से जीएसटी कलेक्शन में 25.8 प्रतिशत की बड़ी ग्रोथ दर्ज हुई और यह अप्रैल 2026 में 57,580 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अप्रैल के दौरान रिफंड 19.3 प्रतिशत बढ़कर 31,793 करोड़ रुपए हो गया। रिफंड एडजस्ट के बाद, नेट जीएसटी कलेक्शन 7.3 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए हो गया।

ईरान युद्ध : भारत के सामने उर्वरक की चुनौती और संभावित समाधान

हरीश दामोदरन

इस महीने की शुरुआत में, 'इंडियन पोटाश लिमिटेड' (आई.पी.एल.) ने 2.5 मिलियन मीट्रिक टन यूरिया के आयात के लिए एक टैंडर जारी किया था। टैंडर में पश्चिमी तट के लिए 935 डालर प्रति टन और पूर्वी भारतीय बंदरगाहों के लिए 959 डालर प्रति टन, (लागत और माल भाड़ा सहित)की न्यूनतम बोली प्राप्त हुई। इसकी तुलना 18 फरवरी को 'राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स' (आर.सी.एफ.) द्वारा जारी एक टैंडर से करें, जिसने पश्चिमी और पूर्वी तट की डिलीवरी के लिए क्रमश: 508 और 512 डालर प्रति टन की बोलियां प्राप्त की थीं।

यह अंतर (दो महीनों के भीतर कीमतों का लगभग दोगुना होना)28 फरवरी से चल रहे 'अमरीका-इसराईल बनाम ईरान संघर्ष' और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण आए आपूर्ति झटकों को दर्शाता है। यह केवल यूरिया तक सीमित नहीं है। 'गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स' द्वारा हाल ही में आयातित 'डाइ-अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.)' की कीमत लगभग 865 डालर प्रति टन थी, जबकि युद्ध-पूर्व स्तर 720 डालर था और पिछले साल इस समय 680 डालर था। वर्तमान अपेक्षित लैंडेड कीमतें 925 डालर प्रति टन होने का अनुमान है।

इसी तरह, तैयार उर्वरकों को बनाने में उपयोग किए जाने वाले मध्यवर्ती उत्पादों की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। आयातित सल्फर की युद्ध-पूर्व कीमतें 550 डालर प्रति टन थीं (अप्रैल 2025 में 300 डालर), आज ये 900 डालर से कम नहीं हैं। अमोनिया भी इसी तरह 850-900 डालर प्रति टन पर है, जो 2025 में औसतन 435 डालर था।

ईरानी हमलों के बाद 'कतर एनर्जी' और सऊदी अरब की 'माडेन' की अमोनिया सुविधाएं बंद हो गई हैं, जिससे हमें मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से स्रोत जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा डी.ए.पी. आपूर्तिकर्त्ता भी था। अब, मोरक्को और जॉर्डन हैं जिन्हें दक्षिण अमरीका और अन्य बाजारों की जरूरतों को भी पूरा करना है।

खरीफ की चुनौती : यह सब आगामी 'खरीफ फसल सीजन' के लिए चुनौती पैदा कर सकता है, जिसकी बुवाई जून से दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होगी। खरीफ 2026 के लिए यूरिया की कुल आवश्यकता 19.4 मीट्रिक टन थी, जबकि अप्रैल की शुरुआत में वास्तविक उपलब्धता मुश्किल से 5.5 मीट्रिक टन थी।

भारत सालाना 39-40 मीट्रिक टन यूरिया की खपत करता है, जिसमें से 30-31 मीट्रिक टन घरेलू स्तर पर उत्पादित होता है और शेष आयात किया जाता है। खाड़ी सहयोग परिषद (जी.सी.सी.) के देश-ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन-युद्ध से पहले भारत के यूरिया आयात का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा थे। भारत के द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) आयात का 60 प्रतिशत से अधिक जो यूरिया के स्वदेशी विनिर्माण के लिए कच्चा माल है, कतर, यू.ए.ई. और ओमान से आता था। हम सामान्य रूप से प्रति माह लगभग 2.5 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करते हैं। मार्च में,एल.एन.जी. आपूर्ति में व्यवधान के कारण हम केवल 1.5 मीट्रिक टन ही कर सके। आई.पी.एल. टैंडर में अनुबंधित 2.5 मीट्रिक टन कार्गो के साथ जहाजों को 14 जून तक रवाना होने के लिए कहा गया था, ताकि खरीफ सीजन के दौरान समय पर पहुंच जाए। आर.सी.एफ. आयात के लिए, अंतिम लोडिंग तिथि (मूल टैंडर के तहत) 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल करनी पड़ी क्योंकि जहाज या तो उपलब्ध नहीं थे या फारस की खाड़ी में होर्मुज समुद्री चैक प्वॉइंट पर फंसे हुए थे।

भारत की वार्षिक उर्वरक बिक्री में यूरिया की 55 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसके बाद डी.ए.पी., एन.पी.के.एस. कॉम्प्लैक्स और एस.एस.पी. का स्थान है। युद्ध के कारण होने वाली कमी से भारी सबसिडी वाले इन उत्पादों, विशेष रूप से यूरिया और डी.ए.पी. की खपत में कमी आ सकती है।

बीज उत्पादक किसानों को 8.2 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि अंतरित

रायपुर। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 3556 बीज उत्पादक किसानों को वित्तीय वर्ष 2024-25 का 8 करोड़ 01 लाख 97 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में ऑनलाईन अंतरित किया। यह राशि मंडी निधि के तहत हितग्राहियों को प्रदाय किया गया। इस मौके पर प्रदेश के सैकड़ों किसान प्रक्रिया केंद्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। मंत्री श्री नेताम ने बीज उत्पादक किसानों से चर्चा कर गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए उनका हौसला बढ़ाया साथ ही निगम के एक वर्ष के उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार विशेष रूप से उपस्थित थीं।

कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों ने अथक मेहनत एवं परिश्रम से बीज उत्पादन किया है। उनके इस मेहनत का फल उन्हें मिले इस उद्देश्य से प्रोत्साहन की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित किया गया। उन्होंने किसानों को धान के अलावा दलहन-तिलहन एवं मिलेट्स और सब्जी-भाजी व अन्य आय मूलक फसलें लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि गरमी के दिनों में धान की खेती से बचना चाहिए। क्योंकि इसमें पानी अधिक लगता है। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के प्रति भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि धान की जगह किसानों को दलहन-तिलहन की खेती करनी चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि बीज की गुणवत्ता पर सरकार की साख जुड़ी होती है। उन्होंने बीज उत्पादक किसानों को ईमानदारी के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन बीज उत्पादन करने की अपील की। उन्होंने किसानों से कहा कि प्रदेश किसानों के लगन और मेहनत से बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के लिए प्राथमिकता पर है। उन्होंने मिल-जुलकर छत्तीसगढ़ को कृषि उत्पादक राज्यों के रूप में आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बीज निगम के अध्यक्ष श्री चन्द्रहास चंद्राकर ने कहा कि यह गौरव का विषय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और मंत्री श्री नेताम के मार्गदर्शन में निगम द्वारा समय पर बीज उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है। आगे भी प्रयास रहेगा कि समय पर किसानों के मेहनत का सम्मान हो। उन्होंनें कहा कि हमारी सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपए प्रति क्विंटल की भाव से धान खरीद कर देश में किसानों का मान बढ़ाया है। उन्होंने इस मौके पर किसानों की ओर से कुछ मांगे भी रखी, जिसका मंत्री श्री नेताम ने गंभीरता के साथ विचार करने का आश्वासन दिया।

समर कैम्प में मिली आध्यात्मिक शिक्षा पूरे जीवन काम आएगी: प्रो. मनोज

रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने कहा कि सभी बच्चों में कुछ न कुछ खुबियाँजरूर होती हैं। आपको उन खूबियों को पहचान कर आगे बढना है। सचिन तेन्दुलकर और अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रतिभा को पहचाना और सही मार्ग चुना। उसी तरह आपको भी सही राह चुनना होगा। इसमें मेडिटेशन आपकी बहुत मदद करेगा। भौतिक शिक्षा तो स्कूलों में आपको मिल ही रही है ब्रह्माकुमारीज के समर कैम्प में आपको आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी।

प्रो. मनोज दयाल आज प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा विश्व शान्ति भवन चौबे कालोनी रायपुर में आयोजित समर कैम्प के उद्घाटन अवसर पर बच्चों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समर कैम्प आपको अपनी प्रतिभा को पहचानने का अवसर देता है। उन्होंने अंग्रेजी के अक्षर चार-सी का उल्लेख करते हुए बतलाया कि सफल होने के लिए इसे जीवन में धारण करें। पहला सी अर्थात करेज यानि निडर व साहसी बनें, दूसरा सी अर्थात कान्फीडेन्स यानि आत्मविश्वासी बनें, तीसरा सी अर्थात चियरफुल अर्थात खुश रहें और चौथा सी यानि कान्सन्ट्रेशन अर्थात एकाग्रता को बढ़ाएं।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रीपल आईटी) के डायरेक्टर डॉ. ओमप्रकाश व्यास ने बच्चों में उत्साह का संचार करते हुए कहा कि यहाँसमर कैम्प में जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी जो कि आगे हर कदम पर आपको मदद करेगा। उनके खुद के व्यक्तित्व में भी ब्रह्माकुमारीज की शिक्षाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह डिजीटल युग का जमाना है जो कि आप बच्चों को भटकाएगा। लेकिन राजयोग मेडिटेशन मन की एकाग्रता को बढ़ाएगा। हमारे पास अधिकतर अभिभावक शिकायत लेकर आते हैं कि बच्चा पढ़ाई में कम और मोबाईल में ज्यादा समय बिताता है। आजकल यह बहुत बड़ी चुनौति बन गई है।

सुशासन तिहार: गांवों में खत्म हो रहा शिकायतों का दौर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार की सुशासन को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सुशासन तिहार के जरिए प्रशासन सीधे ग्रामीणों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। शुक्रवार को ग्राम रिसदा से शुरू हुए इस अभियान ने पहले ही दिन सफलता के नए मानक स्थापित किए हैं।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखना है।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर के बाद भी आवेदकों से फीडबैक लिया जाए कि वे समाधान से संतुष्ट हैं या नहीं।

रिसदा के हाई स्कूल प्रांगण में लगे शिविर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी संवेदनशीलता रही। शिविर में आए 573 आवेदनों में से लगभग आधे का निराकरण राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा की मौजूदगी में अधिकारियों ने तुरंत किया। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकारी मशीनरी अब फाइलों को अटकाने के बजाय सुलझाने पर ध्यान दे रही है। जिन आवेदनों में तकनीकी पेच हैं, उनके लिए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने समय-सीमा (निर्धारित कर दी है।शिविर में केवल शिकायतें ही नहीं सुनी गईं, बल्कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का डिलीवरी सेंटर भी बनाया गया। पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु हेलमेट वितरण और भारत माता वाहिनी को संसाधन भेंट किए गए।

इसी तरह युवाओं को कौशल विकास का सम्मान पत्र और टीबी मुक्त गांव के सरपंचों को महात्मा गांधी की प्रतिमा भेंट कर सामाजिक सहभागिता को सराहा गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर डिजिटल एक्स-रे और तत्काल आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा ने बुजुर्गों और मरीजों को बड़ी राहत दी।

व्यापारियों की सुविधा हेतु तेलीबांधा की यातायात व्यवस्था होगी सुव्यवस्थित

रायपुर। तेलीबांधा क्षेत्र के व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही यातायात समस्याओं के निराकरण हेतु 30 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान यातायात पुलिस और नगर निगम के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने जमीनी स्तर पर ट्रैफिक जाम और पार्किंग की अव्यवस्थाओं का जायजा लिया।

विदित हो कि कुछ दिन पूर्व ही तेलीबांधा क्षेत्र के व्यापारियों के एक समूह ने नगर निगम एवं यातायात विभाग द्वारा किये गये कार्यवाही से आहत होकर चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी से मुलाकात कर क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव और उससे व्यापार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से अवगत कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री थौरानी ने तत्काल यातायात पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क साधा, जिसके फलस्वरूप आज यह संयुक्त निरीक्षण सुनिश्चित हुआ। निरीक्षण के दौरान उपस्थित जनसमूह और अधिकारियों को संबोधित करते हुए चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी ने कहा कि तेलीबांधा रायपुर का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। बढ़ते यातायात और अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर वहां पर लाइट पोल के अंदर गाड़ियां पार्क करना सुनिश्चित किया गया।

सरकार की विदाई तय, घर-घर जाकर बताएंगे भाजपा की नाकामियां: सचिन पायलट

रायपुर। राजधानी में आज प्रदेश कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने राजीव भवन में एक के बाद एक तीन बड़ी बैठकें ली। इस दौरान पायलट समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति पर विस्तार से मंथन किया।

कांग्रेस की बैठक पर सचिन पायलट ने कहा, आने वाले समय में सरकार को घेरने और राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा हुई है। सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था वह मात्र अपने पाखंड और झूठ को अमलीजामा पहनाने के लिए था, उसकी पोल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में हम घर-घर जाएंगे और बीजेपी की नाकामियों को बताएंगे। पायलट ने कहा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार का ढाई साल बचा है। इसके बाद बीजेपी सरकार की विदाई तय है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है।

बैठकों में वरिष्ठ चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सचिन पायलट की पहली बैठक प्रदेश के कांग्रेस विधायकों के साथ हुई। दूसरी बैठक में जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा हुई और तीसरी अंतिम बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में विधायकों, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ अलग-अलग चर्चा हुई, जिसमें संगठन विस्तार, बूथ और ग्राम स्तर तक कमेटियों के गठन और भाजपा के खिलाफ रणनीति पर फोकस किया गया।

बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा महिला आरक्षण रहा। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने साफ कहा कि महिला आरक्षण कानून 2023 में ही पास हो चुका है, लेकिन भाजपा इसे लागू करने में देरी कर रही है और भ्रम फैला रही है। कांग्रेस अब इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है। वार्ड से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यक्रम चलाकर भाजपा के दुष्प्रचार को बेनकाब करने की रणनीति बनाई गई है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

मंत्री अग्रवाल ने स्वर्गीय विवेक अंधारे को दी श्रद्धांजलि

रायपुर। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निज सहायक श्री दीपक अंधारे के चचेरे भाई एवं बंदरचुआ, कुनकुरी निवासी जोगेश्वर अंधारे के सुपुत्र स्वर्गीय विवेक अंधारे के निधन उपरांत आयोजित दशगात्र कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिवारजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने का संबल दिया।

मंत्री अग्रवाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय श्री विवेक अंधारे का अल्पायु में असामयिक निधन अत्यंत पीड़ादायक एवं हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि ऐसी अपूरणीय क्षति की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन सभी को मिलकर परिवार का संबल बनना चाहिए। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

रायपुर कला केंद्र में समर कैंप का भव्य शुभारंभ 135 से अधिक बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की परिकल्पना तथा कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कला केंद्र रायपुर में 15 दिवसीय समर कैंप के प्रथम बैच का भव्य शुभारंभ किया गया। कैंप के पहले ही दिन बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतिभागियों ने रंग-बिरंगी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए नई-नई विधाओं को सीखने की शुरुआत की। समर कैंप के अंतर्गत

बच्चों को गायन, वादन, गिटार, कीबोर्ड, नृत्य, क्ले आर्ट, पेंटिंग, माटी कला तथा ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।यह समर कैंप तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है,1से 15 मई, 16 मई से 30 मई तथा 1 जून से 15 जून तक। अब तक 135 से अधिक बच्चों का पंजीयन हो चुका है, जो इस पहल के प्रति बच्चों और अभिभावकों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। कैंप का समय प्रातः 7ः30 बजे से 9ः30 बजे तक निर्धारित है। प्रारंभिक 30 मिनट में योग और जुंबा कराया जा रहा है, जबकि शेष समय में बच्चों को उनकी रुचि अनुसार विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पुरुषोत्तम पांडेय ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना की राशि 3000 करने की मांग की

रायपुर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के छत्तीसगढ़ प्रदेश संयोजक पुरुषोत्तम पांडेय ने पश्चिम बंगाल के 18 दिवसीय चुनावी दौरे से लौटने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़ों को पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत होने जा रही है और वर्तमान में दिखाए

जा रहे सर्वे आंकड़े जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं।पुरुषोत्तम पांडेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बंगाल की जनता प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भारी लाव-लश्कर और दबाव के कारण डरी हुई थी, जिसके चलते उन्होंने एग्जिट पोल में अपनी सही राय साझा नहीं की। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता शिक्षित है और वह भली-भांति जानती है कि ममता दीदी ने जुमलेबाजी के बजाय विकास के दम पर वोट मांगा है।भाजपा के वादों पर निशाना साधते हुए पुरुषोत्तम पांडेय ने कहा कि जहाँ छत्तीसगढ़ में महिलाओं को महतारी वंदना योजना के तहत मात्र 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं बंगाल की महिलाओं को ममता सरकार पहले से ही 1500 रुपये प्रतिमाह दे रही है।

मेंस परीक्षा 2026 16 से 19 मई नहीं अब होगी 6 से 9 जून को

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने मेंस परीक्षा 2026 की तिथियों में संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने नई तारीखें घोषित करते हुए बताया कि अब परीक्षा 6 जून से 9 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 16 से 19 मई 2026 तक निर्धारित थी। आयोग ने यह निर्णय अभ्यर्थियों की लगातार उठ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया है। कई उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के बीच कम समय मिलने की शिकायत की थी। उनका कहना था कि सीमित समय में व्यापक सिलेबस की तैयारी करना मुश्किल हो रहा है, जिससे प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।

जनप्रिय नेता सांसद बृजमोहन के जन्मदिन पर उमड़ा जनसैलाब

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति के चाणक्य और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का 67वां जन्मदिन इस वर्ष केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक जन-उत्सव बन गया। सेवा, समर्पण और सक्रियता के संगम श्री अग्रवाल के जन्मदिन पर राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल रहा। अपने आवास पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में श्री अग्रवाल ने सपरिवार विधि-विधान से पूजन और हवन कर ईश्वर का आशीर्वाद लिया। उन्होंने आहुतियां अर्पित करते हुए प्रदेश की खुशहाली, सुख-समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पंडितों ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला अगले 24 घंटों तक अनवरत चलता रहा। प्रदेश के कोने-कोने से आए हजारों प्रशंसकों ने अपने प्रिय नेता की लंबी आयु की कामना की। श्री अग्रवाल के समर्थकों ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। गरियाबंद के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन ने बृजमोहन अग्रवाल की 40 वर्षों की ऐतिहासिक राजनीतिक यात्रा को दर्शाते हुए एक विशेष थीम आधारित केक कटवाया। बृजमोहन के समर्थकों ने कहीं 67 किलो का विशाल केक काटा गया, तो कहीं उनके जीवन के 67 वर्षों के प्रतीक स्वरूप 67 अलग-अलग केक काटकर जश्न मनाया गया।

डबल इंजन की रफ्तार, योजनाओं की बौछार- किसान, आदिवासी, महिला और युवा बने केंद्र में

विकास विज़न- सुशासन से जन-जन तक पहुंचती सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते लगभग ढाई वर्षों में शासन की कार्यशैली को लेकर एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश दिखाई देती है। विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने श्सुशासनश् को केवल एक नारा नहीं, बल्कि जमीनी क्रियान्वयन का आधार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सीमित समयावधि करीब 2 वर्ष 4 माह 17 दिन में ही सरकार ने विकास का जो खाका तैयार किया है, उसे भविष्य की बड़ी तस्वीर के रूप में देखा जा रहा है।

प्रदेश की पहचान 'धान का कटोरा' के रूप में रही है, लेकिन इस पहचान को सम्मान देने का काम हालिया नीतिगत निर्णयों में स्पष्ट दिखता है। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय करना केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि अन्नदाताओं के आत्मविश्वास को मजबूत करने की पहल भी है। इसके साथ ही, तेंदूपत्ता संग्राहकों जिन्हें 'हरा सोना' से जुड़ा श्रमिक वर्ग कहा जाता है, के लिए पारिश्रमिक दर को 5500 रुपये करना और चरण पादुका वितरण जैसे निर्णयों ने आदिवासी क्षेत्रों में राहत पहुंचाई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही लगभग 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति देना सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। बेघर और जरूरतमंद परिवारों को छत उपलब्ध कराना सुशासन की पहली सीढ़ी के रूप में देखा गया।राज्य सरकार ने 70 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता राशि देने की पहल की। यह राशि भले सीमित लगे, लेकिन ग्रामीण और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह आर्थिक संबल का काम कर रही है। यह कदम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहे बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों ने असर दिखाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह की रणनीति और संकल्प के साथ 31 मार्च 2026 तक नक्सलमुक्ति का लक्ष्य एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। इससे विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद बढ़ी है। विष्णु देव साय सरकार ने युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोगश् से जुड़े मामलों में जांच कराना सरकार के जवाबदेही वाले दृष्टिकोण को दर्शाता है। साथ ही, खेल गतिविधियों विशेषकर बस्तर व सरगुजा ओलंपिक जैसे आयोजनों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया गया है।

मजदूर दिवस पर गमछा फल भेंट कर मजदूरों का सम्मान किया गया

रायपुर। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ रायपुर जिला के संयोजक बृजेश अग्रवाल के नेतृत्व में आज दिनांक 1 मई अंतरराष्ट्रीय मजदुर दिवस को उत्तर विधानसभा के तेलीबांधा मण्डल में मजदूरों के बीच जाकर शुभकामनाएं प्रेषित की व उनका गमछा फल भेट कर मजदूरों का सम्मान किया गया व साथ ही स्वल्पाहार भी कराया गया और उनकी समस्याएं भी सुनी जिसमें मुख्य रूप उपस्थित से खाद्य नागरिक आपूर्ति के अध्यक्ष केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त संजय वास्तव जी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश के संयोजक संजू नारायण सिंह ठाकुर, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक विकास अग्रवाल, तेलीबांधा भाजपा मंडल अध्यक्ष शेरगिल बेदी, तेलीबांधा मंडल महामंत्री महेश बघेल,भाजपा जिला सहकार्यालय मंत्री अनूप खेलकर, भाजपा शंकर नगर मंडल राम प्रजापति, भाजपा शंकर नगर मंडल महामंत्री सुधीर चौबे , भाजपा शंकर नगर मंडल मंत्री राम तांडी, तेलीबांधा भाजपा पार्षद संतोष साहू,भाजपा पार्षद महेश ध्रुव, एवं भाजपा पार्टी के सम्माननीय पदाधिकारी किशोर दीप, आत्माराम साहू,भवानी कुमार,किशोर बघेल, उपेन्द्र साहू,विजय चौबे, राधे नाग,हुरदा दीप, बिट्टू ,भरत बाघ,मयंक शर्मा,सूरज ध्रुव, व अन्य देवतुल्य कार्यकर्तागण एवं पदाधिकारी मौजुद रहें।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.